RNI NO. RAJHIN/2013/57419

राजस्थान का सर्वाधिक ई-पेपर दैनिक

द पुलिस पोस्ट

अंदोलन नहीं अखबार

जयपुर
गुरूवार
25 जुलाई, 2024

वर्ष: 10 : अंक: 100

जयपुर, जैसलमेर, भीलवाड़ा से प्रसारित

दूरभाष: 01482 : 455184 : पृष्ठ: 08 : मूल्य: 1.50 रुपए

बजट सौगातों के लिए कोटा, ब्यावर व जैतारण की जनता ने जताया मुख्यमंत्री का आभार

विकास की बयार से कोई भी क्षेत्र नहीं रहे अछूता : भजनलाल

द पुलिस पोस्ट

जयपुर(कासं.)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि परिवर्तित बजट 2024-25 में प्रदेश के युवा, महिला, किसान तथा गरीब के उत्थान को लक्ष्य में रखते हुए योजनाओं व कार्यक्रमों की घोषणा की गई है। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य है कि विकास की बयार से राजस्थान का कोई भी क्षेत्र अछूता ना रह जाए। शर्मा बुधवार को मुख्यमंत्री निवास पर बजट सौगातों के लिए कोटा, ब्यावर और जैतारण से आई जनता की धन्यवाद सभा को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अपने क्षेत्र में काम कर रहे जनप्रतिनिधि जनता की आम समस्याओं से वाकिफ होते हैं। साथ ही, जनता भी अपनी मांगों को लेकर उनके पास आती है। राज्य सरकार भी जनप्रतिनिधियों की क्षेत्र से संबंधित विकास की मांगों पर तत्परता से कार्य कर रही है तथा जनता से किए गए सभी वादों को पूरा किया जाएगा।

'एक पेड़ मां के नाम' पर लगाकर देखरेख का भी संकल्प लें

शर्मा ने कहा कि नरेन्द्र मोदी के वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद देश में क्रांतिकारी बदलाव लाए हैं। उन्होंने 'स्वच्छ भारत अभियान' की शुरूआत कर स्वच्छता का संदेश देने और 'बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ' अभियान चलाकर लड़के -लड़कियों का लिंगानुपात सुधारने का महत्वपूर्ण काम किया है। प्रधानमंत्री मोदी न केवल देश को आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से आगे बढ़ाना चाहते हैं अपितु पर्यावरण को संजोने लिए भी वे लगातार जागरूकता ला रहे हैं। उन्होंने कहा कि मोदी ने पर्यावरण दिवस, 5 जून को 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान की शुरूआत की है जिससे अधिक से अधिक लोग पर्यावरण संरक्षण में अपनी भूमिका निभा सकें। उन्होंने जनता से आह्वान किया कि हम सभी एक पेड़ अपनी मां के नाम पर लगाकर उसकी देख-रेख का भी संकल्प लें। मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट में कोटा, ब्यावर व जैतारण के चहुंमुखी विकास के लिए ढेरों सौगातें दी गई हैं। जैतारण में 30 करोड़ रुपये की लागत से समौखी से बलाड़ा, पृथ्वीपुरा से लौटोती, बलुन्दा से खराड़ी, कालब खुर्द से काणूजा, बूटीवास से रास, निमाज से चावण्डिया कलां, कावलिया से आनन्दपुर कालू सड़कों के सुदृढ़ीकरण व चौड़ाईकरण का कार्य करवाया जाएगा। वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरीडोर पर लगभग 110 करोड रुपये व्यय कर संबंधित रेलवे स्टेशनों को दो लेन सड़क से जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि जैतारण में 220 केवी जीएसएस निर्माण, रास-ब्यावर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना, जैतारण में सहायक अभियंता (खनिज) कार्यालय, ब्यावर में अनुसूचित जाति छात्रावास खोले जाएंगे तथा निम्बाज (जैतारण) पशु चिकित्सालय का प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नयन किया जाएगा। शर्मा ने कहा कि औद्योगिक नगरी, कोटा में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट का काम शुरू किया जाएगा। राष्ट्रीय चम्बल घड़ियाल अभ्यारण-कोटा का ईको सेंसेटिव जोन के रूप में चिन्हीकरण कर मास्टर प्लान, रामगंज मण्डी में महिला पुलिस थाना, स्टोन मण्डी एवं स्टोन कलस्टर का उन्नयन सहित अनेक सौगातें कोटा को दी गई हैं। शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार पं. दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय के संकल्प पर काम करते हुए अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति के लिए योजनाओं तथा कार्यक्रमों का संचालन कर रही है तथा उनका उत्थान राज्य सरकार का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि हम सबको भी अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए जरूरतमंदों को केंद्र और राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाने में मदद करनी चाहिए। 'सबका साथ-सबका विकास' की सोच के साथ ही विकसित राजस्थान और विकसित भारत की परिकल्पना साकार होगी। सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री श्री अविनाश गहलोत ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में वर्तमान राज्य सरकार ने अपने पहले ही बजट में विकसित राजस्थान-2047 की रूपरेखा तैयार की है। राज्य सरकार सभी क्षेत्रों व सभी वर्गों के कल्याण के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। कार्यक्रम में विधायक शंकर सिंह रावत ने बजट में ब्यावर को दी गई ढेरों सौगातों के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर जनप्रतिनिधियों ने शर्मा को धन्यवाद देते हुए माल्यार्पण कर उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कोटा, ब्यावर व जैतारण की जनता के साथ संवाद भी किया।

समाज के सभी वर्गों के कल्याण के लिए उल्लेखनीय फैसले

भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार ने समाज के सभी वर्गों के कल्याण के लिए उल्लेखनीय फैसले किए हैं। संकल्प पत्र में किए गए लगभग 45 फीसदी वादे पूरे किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने गेहूं की एमएसपी पर 125 रुपये का बोनस देकर 2,400 रुपये प्रति क्विंटल खरीद मुल्य किया और पीएम किसान सम्मान निधि के तहत देय राशि 6 हजार रुपये से बढ़ाकर 8 हजार रुपये की। सामाजिक सुरक्षा पेंशन में 15 प्रतिशत की बढ़ोतरी, पंचायती राज, नगरीय निकाय व आंगनबाड़ी कर्मियों के मानदेय में 10 प्रतिशत की वृद्धि जैसे अनेक जनकल्याणकारी निर्णय लिए हैं। उन्होंने कहा कि आगे भी इसी तरह जनहितैषी निर्णय लिए जाएंगे तथा संकल्प पत्र में किए गए प्रत्येक वादे को पूरा किया जाएगा।

राज्य सरकार व हुडको के मध्य एमओयू

ऊर्जा उत्पादन में राजस्थान बनेगा सरप्लस स्टेट : भजनलाल शर्मा

द पुलिस पोस्ट

जयपुर(कासं.)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान को ऊर्जा के क्षेत्र में सिरमौर बनाने व पेयजल और सिंचाई के लिए बुनियादी ढांचे के सुदृढ़ीकरण के लिए राज्य सरकार कृतसंकल्पित होकर कार्य कर रही है। इस संकल्प को साकार करने की दिशा में राज्य सरकार सभी आवश्यक वित्तीय संसाधन सुनिश्चित करेगी। उन्होंने कहा कि हाउसिंग एंड अरबन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (हुडको) व राज्य सरकार के बीच हुआ एमओयू विकसित राजस्थान के लक्ष्य की प्राप्ति में मील का पत्थर साबित होगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बुधवार को मुख्यमंत्री कार्यालय पर जैसलमेर सौर ऊर्जा संयत्र के वर्चुअल उद्घाटन समारोह को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी कंपनी रिन्यू (ङ्गह्वद्गङ्ख) की ओर से बुधवार को जैसलमेर में 400 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र से अक्षय ऊर्जा का उत्पादन प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। शेष 200 मेगावाट का उत्पादन अक्टूबर तक प्रारंभ हो जाएगा। शर्मा ने कहा कि इससे राज्य की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में वृद्धि होगी। नवीकरणीय क्षमता जुड़ने से बिजली की लागत कम हो जाएगी जिसके परिणामस्वरूप उपभोक्ताओं के लिए टैरिफ कम होगा और सरकार को बचत भी होगी। इस संयंत्र से राजस्थान डिस्कॉम को बेहद सस्ती दरों पर विद्युत आपूर्ति हो सकेगी। मुख्य सचिव सुधांश पंत ने कहा कि प्रदेश में निवेश के अनुकूल वातावरण तैयार हुआ है। जिला कलक्टर से लेकर मुख्यमंत्री कार्यालय तक निवेश के कार्यों पर तत्परता से कार्य किया जा रहा है ताकि प्रदेश विकसित राजस्थान की ओर तेजी से बढ़ सके। उन्होंने कहा कि राजस्थान में सौर ऊर्जा की अपार संभावनाएं हैं और आज 400 मेगावाट संयंत्र का उद्घाटन इन्हीं संभावनाओं का एक बड़ा परिणाम है। अतिरिक्त मुख्य सचिव ऊर्जा आलोक ने कहा कि इस संयंत्र के संचालित होने से लगभग 350 करोड़ रुपए की बिजली की बचत होगी। बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त अखिल अरोरा, अतिरिक्त मुख्य सचिव मुख्यमंत्री शिखर अग्रवाल, रिन्यू कंपनी के चेयरमैन व संस्थापक सुमंत सिन्हा, हुडको के चेयरमैन संजय कुलश्रेष्ठ सहित ऊर्जा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। हुडको ने राज्य सरकार के साथ एक लाख करोड़ रुपए का एमओयू किया गया, जिसके तहत आगामी 5 वर्षों तक पानी, सिंचाई और बिजली जैसी बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं के लिए राज्य सरकार को प्रति वर्ष 20 हजार करोड़ रुपए का ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। बुधवार को जल जीवन मिशन के लिए हुडको की ओर से आरडब्ल्यूएसएससी को 1577 करोड़ रुपए का चेक सौंपा गया। इस अवसर पर राज्य सरकार व हाउसिंग एंड अरबन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (हुडको) के मध्य महत्त्वपूर्ण एमओयू पर हस्ताक्षर भी किए गए। उल्लेखनीय है कि रिन्यू की ओर से नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में व्यापक निवेश किया जाएगा, जिसके तहत 5500 मेगावाट की नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं और महिंद्रा वर्ल्ड सिटी जयपुर में एक 4 गीगावाट सौर मॉड्यूल निर्माण संयंत्र की स्थापना शामिल हैं। जैसलमेर में स्थापित यह 400 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र इसी निवेश का हिस्सा है।

बुनियादी सुविधाओं के लिए प्रतिबद्ध राज्य सरकार

मुख्यमंत्री ने कहा कि बिजली और पानी की निर्बाध आपूर्ति के क्रम में महत्वपूर्ण प्रगति अर्जित की है। प्रदेश में 28 हजार 500 मेगावाट की अक्षय ऊर्जा व 3325 मेगावाट की थर्मल परियोजनाओं के लिए 1 लाख 50 हजार करोड़ रूपये के निवेश के लिए एमओयू हो चुके हैं। साथ ही, प्रसारण तंत्र के सुदृढ़ीकरण के लिए 10 हजार करोड़ रुपये के निवेश पर हस्ताक्षर भी हुए। राजस्थान ऊर्जा विकास निगम एवं एसजेवीएन के मध्य 600 मेगावाट सौर ऊर्जा परचेज एग्रीमेंट हस्ताक्षरित हो चुका है। उन्होंने बताया कि 8 हजार मेगावाट सौर व 3 हजार 200 मेगावाट कोल आधारित परियोजनाओं के लिए टैरिफ आधारित निविदा प्रक्रिया प्रारम्भ की जा चुकी है। इन परियोजनाओं की स्थापना से 64 हजार करोड़ रूपये का निवेश होगा।

मुख्यमंत्री के नेतृत्व में विकास के नए आयाम स्थापित

उपमुख्यमंत्री व वित्त मंत्री दीया कुमारी ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के मार्गदर्शन में प्रदेश विकसित राजस्थान के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री की कार्यशैली से प्रेरित होकर हम सब कार्य कर रहे हैं और प्रत्येक क्षेत्र में विकास के नए आयाम स्थापित हो रहे हैं। जन स्वास्थ्य व अभियांत्रिकी मंत्री कन्हैया लाल ने कहा कि जल जीवन मिशन में युद्धस्तर पर कार्य किया जा रहा है जिससे आगामी समय में प्रदेश में पेयजल की समस्या का समाधान हो पाएगा। ऊर्जा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) हीरालाल नागर ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार के दौरान विद्युत कुप्रबंधन के कारण राज्य में विद्युत आपूर्ति व उत्पादन अव्यवस्थित हो गया था। लेकिन हमारी सरकार की ओर से ऊर्जा उत्पादन पर ठोस कार्य-योजना बनाकर कार्य किया जा रहा है। किसान, उद्योग व घरेलू उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है।

आनंदपाल एनकाउंटर में पुलिस अफसरों पर चलेगा हत्या का केस

जोधपुर(निसं.)। गैंगस्टर आनंदपाल का एनकाउंटर करने वाले 7 पुलिस अधिकारियों पर हत्या का मुकदमा चलेगा। कोर्ट ने इनके खिलाफ प्रसंज्ञान लेते हुए हत्या की धारा 302 के तहत मुकदमा चलाने और जांच के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को भी खारिज कर दिया है। एसीजेएम सीबीआई कोर्ट ने तत्कालीन चूरू एसपी राहुल बारठ, तत्कालीन एडिशनल एसपी विद्या प्रकाश चौधरी, डीएसपी सूर्यवीर सिंह राठौड़, आरएसी हेड कॉन्स्टेबल कैलाश चंद्र, कॉन्स्टेबल धर्मपाल, कॉन्स्टेबल धर्मवीर सिंह और आरएसी के सोहन सिंह के विरुद्ध मुकदमा चलाने के आदेश दिए हैं। 24 जून 2017 को चूरू के मालासर गांव में एसओजी ने आनंदपाल का एनकाउंटर किया था। एनकाउंटर के बाद से ही इस पर सवाल उठ रहे थे। एनकाउंटर को लेकर सीबीआई ने 2020 में क्लोजर रिपोर्ट पेश की थी, जिसे आनंदपाल की पत्नी राजकंवर ने चैलेंज किया। एसीजेएम कोर्ट में 2020 में प्रोटेस्ट पिटिशन दायर की। कोर्ट में चार साल सुनवाई के दौरान दो डॉक्टर, राजकंवर और आनंदपाल के भाई मंजीत की गवाही हुई। उस आधार पर प्रसंज्ञान लिया गया।

राजस्थान में दो हजार आदर्श आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाएंगे

आंगनबाड़ी केंद्र अब बनेंगे प्ले स्कूल

भजनलाल सरकार ने कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाया

द पुलिस पोस्ट

जयपुर(कासं.)। प्रदेश की भजनलाल सरकार महिला व बाल विकास को लेकर गम्भीर है। राजस्थान में आंगनबाड़ी केंद्रों को प्ले स्कूल की तरह बनाया जाएगा। महिला व बाल विकास राज्य मंत्री मंजू बाघमार ने विधानसभा में यह घोषणा की। उन्होंने बताया कि सरकार महिलाओं और बच्चों के विकास के लिए काम कर रही है। बच्चों को हफ्ते में तीन दिन दूध दिया जाएगा। 2000 आदर्श आंगनबाड़ी केंद्र और 365 ब्लॉक स्तरीय आदर्श आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाएंगे। लाडो योजना से बालिकाओं को सशक्त किया जाएगा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं का मानदेय 10% बढ़ाया गया है।

62000 से ज्यादा आंगनबाड़ी केंद्र, 42 लाख को फायदा

विधानसभा में महिला व बाल विकास विभाग के बजट पर चर्चा हुई। डॉ. बाघमार ने चर्चा का जवाब दिया। इसके बाद सदन ने 32 अरब 12 करोड़ 10 लाख 34 हजार रुपये के बजट को मंजूरी दे दी। मंत्री ने कहा कि राज्य में 365 बाल विकास परियोजनाओं के तहत 62 हजार से ज्यादा आंगनबाड़ी केंद्र चल रहे हैं। ये केंद्र पोषाहार, शिक्षा, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच जैसी सेवाएं देते हैं। इन केंद्रों से करीब 42 लाख गर्भवती महिलाओं, माताओं, किशोरियों और बच्चों को फायदा हो रहा है। डॉ. बाघमार ने बताया कि ग्राम पंचायत स्तर पर पोषण पंचायतें बनाई गई हैं।

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत 50 हजार के लक्ष्य के मुकाबले 85 हजार 500 महिलाओं को लाभ मिला है। इस योजना में अब तक करीब 26 लाख 35 हजार महिलाओं को 959.70 करोड़ रुपये दिए जा चुके हैं।

कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के मानदेय में वृद्धि

राजस्थान सरकार का यह कदम आंगनबाड़ी केंद्रों को और बेहतर बनाने की दिशा में एक सराहनीय प्रयास है। प्ले स्कूल की तर्ज पर विकसित किए जाने से बच्चों को बेहतर शिक्षा और देखभाल मिल सकेगी। साथ ही, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के मानदेय में वृद्धि से उनका मनोबल भी बढ़ेगा। यह योजनाएं महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण में सुधार लाने में मददगार साबित होंगी। राज्य सरकार महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। आंगनवाड़ी केंद्रों को प्ले स्कूल की तर्ज पर विकसित करना इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे बच्चों को बेहतर शिक्षा और देखभाल मिल सकेगी। सरकार की ओर से चलाई जा रही विभिन्न योजनाएं महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण में सुधार लाने में मददगार साबित होंगी। यह कदम निश्चित रूप से राज्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

नेपाल के काठमांडू में प्लेन क्रैश, 18 की मौत

काठमांडू नेपाल की राजधानी काठमांडू में आज एक बड़ा विमान हादसा हो गया. इस हादसे में 18 लोगों की मौत हो गई है. ये प्लेन क्रैश काठमांडू के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हुआ. इस विमान में 19 लोग सवार थे, जिनमें से 18 लोगों की मौत की खबर है. सोलर एयरलाइंस का दुर्घटनाग्रस्त विमान इंजन परीक्षण के लिए पोखरा जा रहा था. नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण के अनुसार, इसमें सवार लोग इंजीनियर और टक्नीशियन थे. स्थानीय मीडिया के मुताबिक, बुधवार काठमांडू में एयरपोर्ट पर हुए विमान हादसे में मारे गए लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं. विमान दुर्घटना में मारे गए 18 लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं. सभी शवों की पहचान सौर्य एयरलाइंस रिलायंस के इंजीनियर और कर्मी के रूप में की गई है. इसकी पुष्टि काठमांडू एयरपोर्ट के प्रमुख प्रेमनाथ ठाकुर ने की है. काठमांडू से पोखरा के लिए उड़ान भरने वाले सौर्य एयरलाइंस के विमान में कुल 19 लोग सवार थे, जिसमें दो कैप्टन दो क्रू मेंबर और 15 यात्री थे इसकी पुष्टि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ़ नेपाल के सूचना अधिकारी ज्ञानेंद्र भुलका ने की है शुरुआती जानकारी के मुतकाबिक, उड़ान भरने के दौरान

विमान फिसलने की वजह से यह हादसा हुआ है. उड़ान भरने के दौरान विमान फिसलने की वजह से यह हादसा हुआ है. इस हादसे की सूचना मिलते ही राहत और बचाव दल तुरंत मौके पर पहुंच गया और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया. जल्द से जल्द विमान में लगी आग बुझाने की कोशिश की गई, ताकि अन्य यात्रियों का पता चल सके. प्लेन में चालक दल और तकनीकी कर्मचारियों समेत 19 लोग सवार थे, जो पोखरा जा रहे थे. एयरपोर्ट के एक प्रवक्ता ने को बताया कि उड़ान भरने के कुछ ही मिनटों के भीतर रनवे से फिसलने के बाद विमान में आग लग गई.

जवाई बाध रेल विकास कमेटी गठित कर सभी को पदाधिकारी बनाया

द पुलिस पोस्ट

शिवगंज जवाई बांध रेल विकास समिति मुख्यालय शिवगंज के नाम से जवाई बांध रेलवे स्टेशन पर यात्री गाड़ियों के स्टेशन के विकास यात्री सुविधाओं में विस्तार तथा रेल से यात्रा करने वालों के लिए शिवगंज सुमेरपुर से आवागमन सुलभ कराने इत्यादि कई महत्वपूर्ण विषयों पर यात्रियों की सुविधा का संकल्प और ध्येय लेकर शिवगंज स्थित श्री जागनाथ महादेव मंदिर परिसर के हाल में प्रबुद्ध जनों की बैठक आयोजित कर चर्चा विचार न की गई और समिति के गठन का निश्चय करते हुए पूर्व डी आर यू सी के सदस्य गंगाराम गोयल को अध्यक्ष खेम सिंह चौधरी ताराराम कुमावत एवं प्रकाश भाटी को उपाध्यक्ष कुंदन म ल राठी को महामंत्री हेमंत अग्रवाल सोनू को सह मंत्री नरेश भाई सिंधी को कोषाध्यक्ष धर्मेंद्र राखेचा को सह कोषाध्यक्ष तथा अशोक भाई माली को प्रचार मंत्री मनोनीत कर यकारिणी के 14 अन्य सदस्यों का चयन किया इसमें समिति का कार्य क्षेत्र तहसील शिवगंज, सुमेरपुर , तथा आहोर रखा गया इन क्षेत्रों के सदस्य भी समिति के सदस्य बन सकेंगे समिति ने शीघ्र ही कार्य समिति का विस्तार करने के उद्देश्य से और सदस्य बढ़ाने का निश्चय किया सदस्य के रूप में बाबूलाल ग्वाल मोहनलाल सोलंकी राजेश मालवीय हनुमान सोनी भवरलाल मालवीय लोहार सुभाष चंद्र अग्रवाल भंवरलाल सुथार नरेश खंडेलवाल मनोनीत किए गए

राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर पर्यावरण प्रेमी ओमप्रकाश कुमावत वेरा जेतपुरा में पौधा-रस्म से स्वागत

द पुलिस पोस्ट

घर घर पौधा -रस्म का प्रचार करेंगे पर्यावरण प्रेमी ओमप्रकाश कुमावत

शिवगंज पोसालिया के समीपवर्ती वेराजेतपुरा मोक्षधाम पर ग्रामीणों द्वारा राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर सम्मानित पर्यावरण प्रेमी ओमप्रकाश कुमावत का वेराजेतपुरा पहुंचने पर पौधा -रस्म संग स्वागत कार्यक्रम का आयोजन रखा गया। इस अवसर ग्राम वासियों ने बरगद, पीपल का पौधा रोपित कर पर्यावरण जागरूकता का संदेश दिया। ग्राम वासियों द्वारा दुपट्टा व साफा पहनाकर स्वागत किया गया। वेराजेतपुरा के प्रतापराम मीणा ,व पन्नालाल वृक्ष मित्र ने बताया कि उदयपुर में पर्यावरण प्रेमी ओमप्रकाश कुमावत को राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर से नवाजा गया है। उस उपलक्ष में पौधा रोपण किया गया है। पौधौ की सुरक्षा व संरक्षण की जिम्मेदारी कानाराम मेघवाल को दी गई। पर्यावरण प्रेमी ओमप्रकाश कुमावत ने ग्राम वासियों का हौसला बढ़ाने के लिए आभार व्यक्त किया। साथ ही नवाचार के तौर पर इस बार नीम ,गुलर,बरगद के बीजो का संग्रहण कर पहाड़ी क्षेत्रों में कंटीले झाड़ियों में बीच उन्हें छोड़ दिया जायेगा ताकि बीज से पौधा तैयार हो सके। भुतपुर्व सैनिक केशुराम मीणा ने भारत माता की जयकारो के साथ कुमावत का स्वागत किया ओर बताया की पहले देश की सेवा अब वनस्पति का संरक्षण ही मेरे जीवन का लक्ष्य है। एक व्यक्ति एक पौधा मिशन द्वारा शिवगंज - सुमेरपुर,सिरोही उपखंड के गौशाला, मोक्षधाम में एक बरगद, एक पीपल,का विशेष अभियान चलाया जाएगा उसके तहत 101 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया। बरगद व पीपल पक्षियों के खाद्य सामग्री का भण्डार है।इसलिए उपस्थित जन को जन्मदिन, पुण्यतिथि, शादी समारोह में पौधा-रस्म अपनाने का संकल्प दिलवाया। इस अवसर पर समाज सेवी प्रतापराम मीणा, वृक्ष मित्र पन्नालाल, खीमाराम मीणा,कानाराम मेघवाल,भुतपुर्व सैनिक केशुराम मीणा, रामलाल मीणा, मोडाराम मीणा, रमेश कुमार परिहार ,देशाराम मीणा, शान्तिलाल मीणा सहित पर्यावरण प्रेमी उपस्थित रहे

अमरपुरा मोक्षधाम में लकड़ी का संकट, दानदाताओ से आग्रह

शहर के सर्वधर्म मोक्षस्थल पर ट्रस्ट की बैठक हुई

द पुलिस पोस्ट

सुमेरपुर शहर की प्राचीन जवाई नदी किनारे स्थित अमरपुरा सेवा मंडल ट्रस्ट सुमेरपुर की एक आवश्यक बैठक संरक्षक व्योवृद्ध गणेश विश्वकर्मा ओर अध्यक्ष प्रकाश अग्रवाल की देखरेख में बुधवार को आयोजित हुई। जिसने स्थानीय मोक्ष स्थल पर शवदाह संस्कार के लिए सुखी लकड़ी के स्टॉक समाप्त हो जाने पर उत्पन संकट को लेकर उपस्थित ट्रस्ट मंडल सदस्यों ने चर्चा कर अनेक प्रस्ताव पारित किए। सचिव संपत मेवाड़ा ने बताया कि इस दौरान सदस्यों ने यह अनुभव किया कि शव के अंतिम दाह संस्कार के दौरान आवश्यकता से अधिक लकड़ी को ले जाने ओर इस्तेमाल के बाद अनुपयोगी लकड़ी को वापस गौदाम में सुरक्षित नही रखने एवं संबंधित लकड़ी को उपेक्षित रखने के मामले को लेकर निराशा जताते हुए । इस प्रसंग पर आग्रह का प्रस्ताव रखा की भविष्य में जो भी परिवार अपने परिजन के अंतिम संस्कार में यहां आवे तो वे लकड़ी की सार संभाल कर उसे सुरक्षित करवाने में योगदान देवे। सुखी लकड़ी को एकत्रित करने के संदर्भ में अशोक सुथार ने प्रस्ताव रखा कि आदिवासी बेल्ट से जुड़े नागरिक एक ट्रॉली जिसमे 35 किवंटल लकड़ी आती है वह पंद्रह हजार में उपलब्ध करवा देते हैं। सदस्य लालचंद चंदेल ने बैठक में ही दो ट्रॉली लकड़ी अपनी तरफ से देने की घोषणा पर उनका आभार जताया। बैठक में सिक्योरिटी गार्ड प्रकाश कुमार वाल्मीकि ने बताया कि अनेक अमरपुरा के लॉकर में अनेक परिजन द्वारा अपने परिजन के पार्थिव फूल रखे हुए हैं, जिनमे कुछ तो महीनों ओर एक दो के तो एक वर्ष से भी ज्यादा हो गया है। जिन्हे विसर्जित के लिए संबंधित परिवार लेकर नही गए हैं। जिस पर सदस्यों ने इस अप्रिय प्रसंग को लेकर खेद जता कर संबंधित के परिजनो को फूल ले जाने के संदर्भ में सूचना मोबाइल द्वारा करने, शव के साथ लाने वाले पुष्प हार इत्यादि को संबंधित परिजनो द्वारा ही नदी में विसर्जन कराने, सुखी लकड़ी को खरीदने के लिए अशोक सुथार एवं दानदाताओ को प्रेरित करने के लिए सरंक्षक विश्वकर्मा ओर अध्यक्ष अग्रवाल को जिम्मेदारी सौंपी गई। वही मोक्षधाम के नीचे गंदे पानी की पाइप लाइन लगवाने और ढलान बनवाने के लिए नगर पालिका सुमेरपुर से कार्य करवाने के लिए पार्षद चताराराम मेघवाल को दायित्व दिए गए। बैठक में सदस्य सतपाल मेहरा, सूरजमल विश्वकर्मा,भीखाराम माली ने भी उपयोगी विचार रखे। इस अवसर पर अनेक अन्य रचनात्मक प्रस्ताव के को भी सर्व सम्मति से पारित किया गया। बैठक के दौरान उपस्थित सभी सदस्यो ने अमरपुरा सेवा मंडल परिसर, लकड़ी के पांचों गोदाम, शव दाह स्थल का अवलोकन कर यहां और गेट पर आवश्यक सूचना, सरंक्षण चेतावनी आदि को अंकित करवाने की हिदायत गार्ड को दी गई।

केन्द्रीय बजट से कर्मचारी हताश एवं निराश - गहलोल

द पुलिस पोस्ट

शिवगंज- लोकसभा में वित्तमंत्री द्वारा 2024-25 के प्रस्तुत बजट को राजस्थान शिक्षक संघ (प्रगतिशील) की प्रदेश कार्यकारिणी की और से प्रदेश मुख्यमहामंत्री धर्मेन्द्र गहलोत ने बजट को कर्मचारी विरोधी बताकर शिक्षको एवं कर्मचारियों द्वारा रखी गई सभी माँगो को खारिज करने के फैसले पर गहरी नाराजगी जताई है। शिक्षक नेता धर्मेन्द्र गहलोत ने बजट पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि केन्द्र सरकार ने आँठवा वेतन आयोग, पुरानी पेन्शन योजना को बहाल करने, महंगाई कम करने, सरकारी क्षेत्र में रोजगार बढ़ाने, इन्कम टैक्स की सीमा छुट कम से कम 10 लाख करने, साथ ही प्रत्येक शिक्षक के साथ अन्य मंत्रालयिक कर्मचारी भी आयकर के दायरे में लाने का प्रयास की संगठन एवं कर्मचारी वर्ग में बजट को लेकर हताशा एवं निराशा स्पष्ट रूप से नजर आ रही है। कुल मिलाकर बजट कर्मचारी विरोधी नजर आ रहा है। जस तरह से कर्मचारी इस बार नजर घडाए हुए थे कि ओ.पी. एस. एवं आंठवा वेतन आयोग गठन की घोषणा सहित एन.पी.एस. का पैसा राज्य सरकार को मिलने के अलावा फ्रिज किये गये महंगाई भत्ता देने की उम्मीद पर पानी फिर गया है। अब कर्मचारियों को किसी भी तरह की आस नजर नहीं आ रही है। बजट को लेकर कर्मचारी वर्ग में जबरदस्त आक्रोश व नाराजगी स्पष्ट रूप से नजर आ रही है।

165 वे आयकर दिवस पर बालिकाओं को आयकर कर प्रणाली की जानकारी दी आयकर दिवस पर प्रतियोगिता आयोजित

द पुलिस पोस्ट

सिरोही - आयकर विभाग सिरोही की टीम ने आयकर दिवस पर राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय सिरोही की बालिकाओं को भारतीय आयकर प्रणाली की जानकारी दी। कार्यक्रम प्रभारी गोपाल सिंह राव के अनुसार दीपाराम धणदे आयकर अधिकारी सिरोही ने बालिकाओं को आय के अनुसार आयकर, बढ़ती आय से बढ़ते आयकर,कर से देश के विकास पर विस्तार से समझाया। देश के 165 वें आयकर दिवस पर निबन्ध प्रतियोगिता का आयोजन किया। बालिकाओं ने आयकर की आम जन में भूमि का तथा आयकर का राष्ट्र निर्माण में योगदान विषय पर निबंध लिखा। प्रतियोगिता प्रभारी गोपाल सिंह राव तथा निर्णायक वाणिज्य व्याख्याता श्रीमती सुमन कुमारी, महेंद्र कुमार प्रजापत तथा श्रृद्धा सिंदल रहे ।तीन विजेता प्रतिभागियों को आयकर विभाग सिरोही की तरफ से पुरूस्कृत किया जाएगा। कार्यक्रम में आयकर अधिकारी सिरोही दीपाराम धणदे आयकर निरीक्षक महेश कुमार रावल , कर सहायक जवाना राम परिहार, महेंद्र कुमार मीणा, संजय कुमार कुम्हार ,नरपत लाल परिहार, विद्यालय की और से वरिष्ठ व्याख्याता अनीता चौहान, वर्षा त्रिवेदी, देवी ,जया दवे, दिनेश कुमार सुथार, कल्पना चौहान, रीना कोटेसा, ममता कोठारी,सहायक प्रशासनिक अधिकारी विजय कुमार मीणा, शैफाली सिंह गहलोत, कीर्ति सोलंकी व प्रतिभागी बालिकाएं उपस्थित रही।

घर में घुस कर महिला, 2 बेटियों के साथ मारपीट:पीड़िता का आरोप- 80 हजार की नगदी और जेवरात से भरा बैग ले गए आरोपी

द पुलिस पोस्ट

नदबई। नदबई में घर में सो रही महिला और उसकी 2 बेटियों के साथ बदमाशों द्वारा मारपीट करने और करीब 80 हजार रुपए की नगदी, जेवरात से भरे बैग को चोरी करने का आरोप लगते हुए 6 लोगों के खिलाफ नदबई थाने में मामला दर्ज हुआ है। पुलिस ने बताया की वेयर हाउस रोड वार्ड नम्बर 31 नदबई निवासी प्रवेश पत्री चन्द्रशेखर जाट ने मामला दर्ज कराया है की पीड़िता अपने घर के अंदर थी, तभी हिंगोली थाना कुम्हेर निवासी आरोपी बहादुरसिंह पुत्र पतिराम, ममता देवी पत्नी बहादुरसिंह अपने बेटाझबेटियों समेत एक अन्य के साथ गालियां देते हुए डंडो से लैस होकर घर के अंदर घुस आए और पीड़िता के साथ मारपीट की। पीड़िता ने आरोप लगाया है की चीख चिल्लाहट पर उसकी दोनों बेटियों ने बीच बचाव करने की कोशिश की, तो आरोपियों ने उनके साथ भी मारपीट की। पीड़िता ने दर्ज रिपोर्ट में बताया है की आरोपी उसके घर से बैग को उठाकर ले गए। जिसमें 80 हजार रुपए नगद, चार चूडिया, कोलर, लर, पैंडल, 6 अंगुठी, टीका और सोने की बारी, दो जोडी पायजेब और एक कोधनी चांदी के रखे हुए थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

शिक्षा सप्ताह खेलकूद दिवस मनाया

द पुलिस पोस्ट

शिवगंज राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् जयपुर के निदेर्शानुसार राउमावि दादावाड़ी शिवगंज के संस्था प्रधान डॉ हनवंतसिह मेड़तिया के मार्गदर्शन में विद्यार्थियों के लिए शिक्षा सप्ताह तृतीय दिवस खेल दिवस के रूप में मनाया गया। विद्यालय की सहशैक्षणिक गतिविधियों के प्रभारी वरिष्ठ अध्यापक रमेशचन्द्र आगलेचा ने संवाददाता को बताया कि व्याख्याता बलवंतसिंह राठौड़ के सान्निध्य में विद्यार्थियों के लिए पारम्परिक खेलों का आयोजन करवाया गया जिसमें शतरंज, गिल्लीडंडा, संतोलिया- मालदड़ी, लट्टू, कंचे सहित बैडमिंटन, कबड्डी व विभिन्न प्रकार के शारीरिक व मानसिक विकास वृद्धि के खेलों का आयोजन करवाया गया। शारीरिक शिक्षक श्रवणसिंह देवड़ा व अध्यापिका चंदा मीणा ने छात्र- छात्रा वर्ग में खिलाड़ियों का विभाजन किया। खेल प्रतियोगिता में व्याख्याता कांतिलाल , रमेशककुमार परिहार, राजेन्द्रकुमार गेहलोत, जोराराम मेघवाल, मंजू मीणा सहित विद्यालय स्टाफ का सहयोग रहा।

लालसोट विधायक रामबिलास से जान का खतरा बताकर मांगी सुरक्षा:पीड़ित बोला: जान से मारने की धमकी; हाईकोर्ट ने सिक्योरिटी के दिए आदेश

द पुलिस पोस्ट

जयपुर। जवाहर नगर में रहने वाले एक व्यक्ति ने लालसोट विधायक रामबिलास मीणा से जान का खतरा बताकर हाईकोर्ट में सुरक्षा की गुहार लगाई हैं। पीड़ित संतोष काला की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने जवाहर नगर एसएचओ को 48 घंटे में सुरक्षा देने पर निर्णय लेने के लिए कहा हैं। अदालत ने याचिकाकर्ता को 24 जुलाई को थानाधिकारी के समक्ष पेश होकर अपनी शिकायत पेश करने के निर्देश भी दिए। याचिका में कहा गया था कि उसने सुरक्षा को लेकर थानाधिकारी सहित पुलिस कमिश्नरेट में गुहार लगाई थी। लेकिन उसके सुरक्षा प्रदान नहीं की गई। याचिकाकर्ता का कहना है कि विधायक रामबिलास मीणा सत्तारूढ़ पार्टी का विधायक हैं। ऐसे में पुलिस उसकी सुनवाई नहीं कर रही है। विधायक से लिए थे 40 लाख रुपए उधार याचिकाकर्ता के अधिवक्ता गोपाल सिंह बारहठ ने बताया कि याचिकाकर्ता ने अपने व्यापारिक जरूरत के लिए एक व्यक्ति के जरिए पिछले साल विधायक रामबिलास से चालीस लाख रुपए नकद उधार लिए थे। याचिकाकर्ता ने समय-समय पर उधार लिए पूरे रुपए भी लौटा दिए। लेकिन, विधायक बनने के बाद रामबिलास ने चुकाई गई राशि को ब्याज बताकर मूल राशि वापस मांगी। इसके बाद जनवरी माह में याचिकाकर्ता के कार्यालय आकर धमकी दी और 25 लाख रुपए के दो चैक आगामी तिथि के ले लिए। याचिका में कहा गया कि चेक बाउंस होने पर विधायक के गुर्गो ने आकर उसे जान से मारने की धमकी दी और मकान व ऑफिस पर कब्जा करने की बात कही।

दो पत्र तारीख एक आयुक्त के हस्ताक्षरों में भिन्नता वाले पत्र सोसल मीडिया पर वायरल

द पुलिस पोस्ट

सिरोही, सोसल मीडिया पर नगर परिषद सिरोही द्वारा जारी वायरल हुए पत्रों में हस्ताक्षरों को लेकर चर्चा शुरू हो गई है नगर परिषद सिरोही के दोनों पत्रों के जारी होनी की एक ही दिनांक 23 जुलाई 2024 लेकिन दोनों पत्रों पर आयुक्त के हस्ताक्षरों में काफी भिन्नता नजर आ रही है एक पत्र नगर परिषद सिरोही की बोर्ड बैठक को लेकर दस बिन्दुओं वाले ऐजेण्डे का 23 जुलाई को जारी पत्र जिसमें आयुक्त के पदनाम पर हस्ताक्षर वाली जगह पर एक लकिर के रूप में हस्ताक्षर दिखाई दे रहे हैं पत्र के उपर की बजाय निचे डिस्पेच नंबर 4263,4270 दिनांक 23जुलाई 2024 नजर आ रही है दुकानों मकानों के बार स्थाई अस्थाई अतिक्रमणों को लेकर जारी आम सूचना वाले पत्र के उपरी भाग पर डिस्पेच नंबर 902 एवं नीचले भाग पर 903 दिनांक 23 जुलाई 2024 जारी किया हुआ सोसल मीडिया पर वायरल हो रहा है आखिर नगर परिषद द्वारा जारी दो पत्रों में आयुक्त के हस्ताक्षरों में भिन्नता क्यों दिखाई दे रही है इसका जवाब तो आयुक्त नगर परिषद सिरोही ही बता सकते हैं!

गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करने बना फर्जी डीएसपी : पुलिस पकड़ने पहुंची तो बोला: मैं डिप्टी; काले जूतों से पकड़ा गया

द पुलिस पोस्ट

झुंझुनूं। गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करने के लिए फर्जी डीएसपी बनकर घूम रहे युवक को को पुलिस ने धर दबोचा। आरोपी ने थ्री स्टार वर्दी पर अपने नाम की नेमप्लेट भी लगा रखी थी। बाइक पर भी उसने पुलिस का स्टिकर चिपकाया हुआ था। मामला झुंझुनूं जिले के कोतवाली थाना इलाके का है। आरोपी को मंगलवार रात थाना इलाके के इंदिरा नगर से पुलिस ने गिरफ्तार किया। कोतवाली थाना के एएसआई मुलायम सिंह ने बताया- मंगलवार रात 8 बजे थाना इलाके के इंदिरा नगर में धन्वंतरि हॉस्पिटल के पास सार्वजनिक पार्क के पास बिना नंबर की बाइक पर बैठा आरोपी किसी का इंतजार कर रहा था। बाइक पर पुलिस का स्टिकर लगी देखकर स्थानीय निवासी ने पुलिस को सूचना दी। सूचना के मुताबिक आरोपी कई दिन से इलाके में वर्दी पहन कर बिना नंबर की बाइक लेकर घूम रहा था। इस दौरान किसी कंट्रोल रूम में सूचना दे दी। सूचना पर इलाके में गश्त कर रहे कोतवाली थाने के हेड कॉन्स्टेबल धर्मपाल मौके पर पहुंचे। हेड कॉन्स्टेबल धर्मपाल ने बताया- हम मौके पर पहुंचे तो आरोपी बिना नंबर की बाइक पर खाकी पैंट, काले जूते और काली टीशर्ट पहने बैठा था। बाइक पर पुलिस का स्टिकर लगा रखा था। पुलिस की गाड़ी आते देख वह सकपका गया। उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। वह वहां से जाने लगा तो पीछा कर रोक लिया। उसके पास एक बैग भी था। उससे नाम पूछा तो बताया कि मैं निशांत हूं। डिप्टी हूं। पूछा कौन से इलाके के डिप्टी हो तो जवाब नहीं दे पाया। आई कार्ड मांगा तो वह भी नहीं था। उससे बाइक के कागज मांगे तो वे उसके पास नहीं थे। उसके काले जूते देखकर शक पुख्ता हो गया था। बैग की तलाशी ली तो वर्दी मिली, जिस पर थ्री स्टार लगे थे। नेमप्लेट भी लगाई हुई थी। कोतवाली लाकर सख्ती की तो उसने बताया- मेरा नाम निशांत मील (24) पुत्र राजेंद्र मील है। मैं बाकरा गांव (झुंझुनूं) का रहने वाला हूं। गर्लफ्रेंड पर इंप्रेशन जमाने के लिए मैं पुलिस की वर्दी में डीएसपी बनकर घूम रहा था। मैं ग्रेजुएट हूं, बेरोजगार हूं और गांव में रहकर कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहा हूं। पिता राजेंद्र मील किसान हैं।

काले जूतों से पकड़ा गया

एएसआई मुलायम सिंह ने बताया- फर्जी डीएसपी बनकर घूम रहा निशांत पुलिस के नियम नहीं जानता था। पुलिस का वर्दी और पोशाक का नियम होता है। पुलिस के उच्च अधिकारी कभी काले रंग के जूते नहीं पहनते। उनके जूतों का रंग लाल (गहरा भूरा)

होता है। डीएसपी की वर्दी पर कभी थ्री स्टार नहीं होते। डीएसपी की वर्दी पर बाजू पर आरपीएस लिखा होता है। निशांत ने वर्दी तो सिलवा ली लेकिन उस पर तीन स्टार लगा लिए और राजस्थान पुलिस लिखवा रखा था। ऐसा नहीं होता। बात करते हुए वह घबरा रहा था। उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं। इससे वह पकड़ में आ गया।

बैंक ऑफिसर ने ट्रेन के आगे कूदकर दी जान:पंजाब से ट्रांसफर होकर आया था अलवर, पत्नी दो साल से अलग रह रही

द पुलिस पोस्ट

अलवर। अलवर में मंगलवार रात बैंक अधिकारी ने सुसाइड कर लिया। वह एक महीने पहले की पंजाब से ट्रांसफर होकर अलवर आए थे। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि गृहक्लेश के कारण बैंक अधिकारी ने अपनी जान दी। पुलिस की सूचना पर परिजन अलवर आए। जानकारी अनुसार- जयपुर के दादी का फाटक निवासी भोजराज वर्मा (31) ने ट्रेन के आगे कूदकर सुसाइड कर लिया। अलवर में मंडी मोड पीएनबी ब्रांच में एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर थे। शहर के अंबेडकर नगर में किराए के मकान में रहते थे। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि पत्नी से हो रही कलह से तंग आकर जान दे दी। बैंक अधिकारी की पत्नी करीब 2

साल से अलग रह रही है और सरकारी क्लर्क है। उनका पीहर सांगानेर (जयपुर) है। मृतक के एक 3 साल का बेटा है।

क्लासरुम में स्टूडेंट फंदे पर लटकी, 6 दिन बाद मौत:इलाज के दौरान तोड़ा दम, कॉलेज की लड़कियां लेकर गई थी हॉस्पिटल

द पुलिस पोस्ट

जोधपुर। जोधपुर के कमला नेहरु महिला महाविद्यालय के क्लासरुम में फंदे पर लटकी स्टूडेंट ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। सुसाइड करती स्टूडेंट को 17 जुलाई को कुछ गर्ल्स ने देख लिया था, जिसके बाद उसे फंदे उतारकर पुलिस की चेतक गाड़ी में महात्मा गांधी हॉस्पिटल लेकर गई थी। 6 दिन बाद युवती ने बुधवार रात 11 बजे दम तोड़ दिया। रतकुडिया हाल में खोखरिया निवासी रामप्रकाश पुत्र छोटुराम कुमोर ने उदय मंदिर थाने में मामला दर्ज करवाया कि उसकी बेटी नीतू ने केन हॉल में क्लासरुम में फांसी लगा ली थी। वहीं केन हॉल प्रशासन का कहना है कि कॉलेज में क्लासेज नहीं लग रही है। फिर भी कुछ गर्ल्स कॉलेज आती है और क्लासरुम में बैठती है। घटना के दिन पुलिस की चेतक गाड़ी केन हॉल के गेट के बाहर खड़ी थी। तब गर्ल्स ने पुलिस को सूचित किया और उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। नीतू की हालत नाजुक थी और पांच दिन बाद उसने दम तोड़ा।

गोतस्करी के शक में युवक की गोली मारकर हत्या:परिवार का आरोप- पुलिस ने मारा; एसपी बोले- पिकअप में बैठे-बैठे गोतस्करों ने फायर किया

द पुलिस पोस्ट

भरतपुर। युवक के सीने में गोली मारकर हत्या कर दी गई। वह फसल को नुकसान पहुंचा रही गायों को टेम्पो में लोड कर गांव से दूर छोड़ने जा रहा था। परिवार वालों का आरोप है कि गो-तस्करी के शक में पुलिस ने गोली मार दी है। इसकी खबर मिलते ही युवक के परिवार वाले थाने पहुंच गए और हंगामा किया। मामला डीग जिले के कुम्हेर इलाके का है।

पुलिस पीछा करती रही, आरोपी फरार

डीग एसपी राजेश मीणा ने बताया- मंगलवार देर रात करीब 1 बजे कुम्हेर पुलिस को गायों से भरी पिकअप जाने की सूचना मिली थी। पुलिस और कुछ लोगों ने पिकअप का पीछा किया। रात करीब 2 बजे पिचूमर बस स्टैंड के पास चुंगी पर दूसरी पिकअप खड़ी दिखाई दी। उसमें गोतस्कर थे। गाड़ी में बैठे-बैठे गोतस्करों ने फायर किया और गोली गायों से भरी पिकअप चल रहे संदीप प्रजापत (20) पुत्र हरिश्चंद्र को लगी। उसकी मौत हो गई। संदीप सोनगांव का रहने वाला था। वह पिता के साथ खेती करता था। पुलिस ने आरोपियों का पीछा किया, पर वो फरार हो गए।

पुलिस ने फोन कर चचेरे भाई को जानकारी दी

संदीप के चचेरे भाई सोनगांव निवासी मानसिंह ने बताया- संदीप अपने माता-पिता का इकलौता बेटा था। उसने 1 महीने पहले नया लोडिंग टेम्पो लिया था। बुधवार सुबह करीब 7 बजे पुलिस का फोन आया। बताया कि संदीप की गोली लगने से मौत हो गई। संदीप मेरा छोटा भाई था। पुलिस कह रही है कि संदीप को हमारी गोली नहीं लगी है। हमें पुलिस पर शक है। शव डीग हॉस्पिटल की मॉच्युर्री में है।

किसानों की गायें फसल खराब कर रही थीं

सोनगांव के सरपंच प्रतिनिधि मुंशीलाल ने बताया- सोनगांव में कुछ किसानों की गायें फसलों को आए दिन खराब कर देती थीं। गांव के संदीप प्रजापत और नरेश कुमार (28) ने गांव के ही दो किसानों (हरचंद और विष्णु) की गायों को देर रात 1 बजे टेम्पो में लोड किया। इन गायों को गांव की सीमा से दूर छोड़ने के लिए निकले थे।

गोरक्षकों ने बाइक से पीछा किया था

सोनगांव के सरपंच प्रतिनिधि मुंशीलाल ने बताया- इस दौरान गोरक्षकों के दल ने बाइक पर दोनों का पीछा करना शुरू कर दिया। गोरक्षकों ने कुम्हेर पुलिस को भी फोन कर दिया। पुलिस की टीम भी उनका पीछा करने लगी। रात 2 बजे पिचूमर बस स्टैंड के पास संदीप पर फायर हुआ और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। अब गोली पुलिस ने चलाई, गोरक्षक दल के किसी सदस्य ने चलाई या गोतस्करों ने, इसकी जांच की मांग कर रहे हैं।

साथी पुलिस हिरासत में

संदीप की मौत की सूचना मिलते ही परिवार वालों के साथ गांव वाले कुम्हेर थाने पर पहुंच गए। प्रजापत समाज के लोग भी जुटे हुए हैं। इस पूरे मामले के निष्पक्ष जांच की मांग की जा रही है। संदीप के दूसरे साथी नरेश को कुम्हेर पुलिस ने कस्टडी में ले रखा है। कुम्हेर थाना अधिकारी अध्यात्म गौतम ने कहा- नरेश से पूछताछ की जा रही है। जांच की जा रही है। हालांकि घटना के बाद से ही नरेश को पुलिस ने कुम्हेर थाने में बैठा रखा है। वह घटना का चश्मदीद है। शुरूआत में पुलिस ने जानकारी दी थी कि नरेश को डिटेन किया गया है। वि?वाद बढ़ता देखकर एसएचओ ने सफाई में कहा कि नरेश को हिरासत में नहीं लिया गया है, सिर्फ पूछताछ की जा रही है। मामला दर्ज होने के बाद कार्रवाई आगे बढ़ेगी।

सड़क पर उतरेगा प्रजापत समाज

श्रीयादे महाप्रजापति विकास सेवा समिति के सदस्य दिगंबर सिंह प्रजापत ने कहा- संदीप की गोली मारकर हत्या की गई है। इससे प्रजापत समाज में आक्रोश है। न्याय के लिए हम थाने के सामने जुटे हैं। अभी पोस्टमार्टम होना बाकी है। परिजन हत्या का मुकदमा दर्ज कराएंगे। प्रशासन से हमारी मांग है कि किसी भी सूरत में अपराधियों को छोड़ा न जाए। न्याय की गुहार कर रहे हैं। न्याय नहीं हुआ तो प्रजापत समाज सड़क पर उतरेगा और उग्र आंदोलन करेगा। इस मामले में आईजी राहुल प्रकाश ने कहा- मामले की निष्पक्ष जांच करेंगे। जो दोषी होगा उसे सजा मिलेगी।

महिला की संदिग्ध मौत!:घर में फांसी लगाई, पीहर पक्ष ने मारपीट व परेशान करने के आरोप लगाए

द पुलिस पोस्ट

कोटा। शहर के उद्योग नगर थाना क्षेत्र में एक विवाहिता की सन्दिग्ध मौत का मामला सामने आया है। विवाहिता अपने कमरे में फांसी पर लटकी मिली। जिसे परिजन इलाज के लिए निजी हॉस्पिटल लेकर गए थे। विवाहिता के पीहर पक्ष वालों ने पति पर मारपीट का आरोप लगाया है। विवाहिता नीरू प्रजापति (32) अपने पति महेंद्र व दो बच्चों के साथ शिवाजी नगर कंसुआ इलाके में रहती थी। भाई अभिषेक ने बताया कि उसकी दीदी की शादी साल 2009 में कोटा निवासी महेंद्र के साथ हुई थी।जीजा महेंद्र के कैथून में ईंट भट्टे का काम है। जीजा शराब का आदि है।अक्सर शराब के नशे में दीदी नीरू से मारपीट करता था। कई बार दीदी ने फोन पर मारपीट की बात बताई। मारपीट से परेशान होकर कुछ महीने पहले दीदी अपने मायके छबड़ा आ गई थी। महेंद्र छबड़ा आया लेकिन घर नहीं गया। होटल में दीदी को बुलाकर मारपीट की। फिर उसे अपने साथ कोटा ले आया। आज सुबह साढ़े 10 बजे करीब जीजा के साथी ने फोन करके दीदी के फांसी लगाने की सूचना दी। परिवार सहित छबड़ा से कोटा आए। दीदी के शरीर पर चोट के निशान थे। पुलिस ने तुरत फुरत पंचनामें की कार्रवाई की। फिलहाल पुलिस ने हमारी शिकायत नहीं ली है। जीजा की मारपीट से दीदी डिप्रेशन में थी। पति महेंद्र ने बताया वो वो सुबह ईंट भट्टे पर चला गया था। साढ़े 9 बजे करीब छोटे भाई ने फोन पर जानकारी दी। पति पत्नी के बीच छोटी छोटी बात पर कहासूनी होती रहती है। नीरू ने किस तनाव में फांसी लगाई। इस बारें में जानकारी नहीं। उद्योगनगर थाना एएसआई हरवीर सिंह ने बताया कि महिला ने फांसी लगाई थी। परिजन उसे उतारकर निजी हॉस्पिटल लेकर गए। वहां से उसे एमबीएस हॉस्पिटल रेफर किया गया। पति पत्नी में थोड़ी बहुत कहासूनी होने की बात सामने आई है। पंचनामें की कार्रवाई में महिला का भाई मौजूद था।अभी पीहर पक्ष ने शिकायत नहीं दी। पीहर पक्ष के बयान लिए जाएंगे। शव का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है।

कलेक्शन के 9 लाख लूटने चलती बाइक पर मारा सरिया:युवक का सिर फटा

द पुलिस पोस्ट

पाली। पाली में बुधवार दिनदहाड़े एक बाइक पर आए बदमाशों ने युवक के सिर पर सरिए से वार कर उससे रुपयों से भरा बैग लूटने की कोशिश की। युवक रुका नहीं और बाइक दौड़ा दी। जिससे बदमाश लूट की वारदात को अंजाम देने में कामयाब नहीं हो सके। घायल युवक को साथी इलाज के लिए पाली के बांगड़ हॉस्पिटल लेकर पहुंचे। जहां उसका इलाज जारी है। पुलिस के अनुसार- भीलवाड़ा जिले के अंटाली गांव हाल पाली के प्रताप नगर में रहने वाला 26 साल का महेन्द्र रेबारी पुत्र मांगीलाल रेबारी सरस डेयरी के बूथों से दूध के कलेक्शन के रुपए बैंक में जमा करवाने का काम ठेकेदार के पास करता है। हमेशा की तरह बुधवार को भी वह 9 लाख 15 हजार रुपए बैग में डालकर मिल गेट चौकी के सामने स्थित पीसीसीबी बैंक में जमा करवाने जा रहा था। इस दौरान ओवरब्रिज पर पीछे से एक बाइक पर आए तीन युवकों में से एक ने चलती बाइक में उसके सिर पर लोहे के पाइप से वार किया और कुछ आगे जाकर रुक गए। पाइप लगने

महेन्द्र के सिर से खून बहने लगा। लेकिन उसने खुद को संभाला और यूटर्न लेकर बाइक दौड़ा दी और ओवरब्रिज के निकट ही अपने एक परिचित के घर में घुस गया। ऐसे में बदमाश लूट की वारदात को अंजाम देने में कामयाब नहीं हो सके। घायल महेंद्र को साथी उपचार के लिए पाली के बांगड़ हॉस्पिटल लेकर पहुंचे जहां उसका इलाज करवाया गया।

पीड़ित बोला- एक बाइक पर थे तीन, मुंह रूमाल से बांध रखा था

घटना को लेकर पीड़ित महेंद्र रेबारी ने बताया कि बाइक पर तीन युवक थे। जिन्होंने मुंह रूमाल से बांध रखे थे। चलती बाइक पर उस पर पाइप से हमला किया गया। जिससे उसे चक्कर आने लगे लेकिन खुद को संभालते हुए उसने वापस बाइक घूमा दी। बदमाशों ने उसका पीछा भी किया। लेकिन ओवरब्रिज से नीचे उतरते ही अपने एक परिचित के घर में घुस गया। जिससे बदमाश लूट की वारदात को अंजाम देने में कामयाब नहीं हो सके।

एसएचओ बोली- मामले की जांच कर रहे हैं

मामले में औद्योगिक थाने की एसएचओ पाना चौधरी ने बताया कि लूट की वारदात होने की सूचना मिली है। जिसकी जांच की जा रही है। उसके बाद आगे की कार्रवाई करेंगे।

हिस्ट्रीशीटर का अवैध कब्जा तोड़ा, फैक्ट्री सीज की:ऑपरेशन जमीदोंज के तहत कार्रवाई; अनवर पर 27 मामले दर्ज हैं

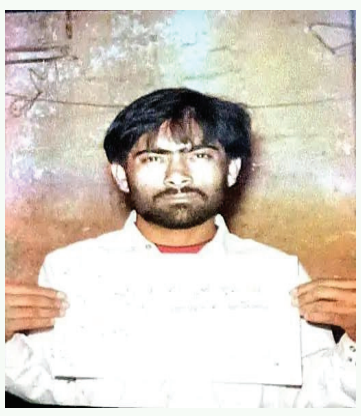

द पुलिस पोस्ट

बाड़मेर। राजस्थान पुलिस हिस्ट्रीशीटर व तस्करों के अवैध कब्जे व संपतियों को तोड़ रही है। बालोतरा पुलिस, नगर परिषद, डिस्कॉम व वन विभाग की टीमों ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए हिस्ट्रीशीटर के अवैध कब्जे को ध्वस्त किया। यह कब्जा बालोतरा शहर के सरस डेयरी के सामने के एरिया में किया हुआ था। साथ ही

जमीन पर संचालित अवैध कपड़ा धुलाई फैक्ट्री को सीज किया। परिसर में जमा अवैध लकड़ियों को भी बरामद कर अलग-अलग मामले दर्ज किए गए हैं। इस दौरान डिस्कॉम टीम ने बिजली कनेक्शन काटने की कार्रवाई की। बालोतरा एसपी कुंदन कंवरिया ने बताया कि यह कार्रवाई पुलिस मुख्यालय की ओर से दिए गए निदेर्शानुसार जिले में चलाए जा रहे ऑपरेशन जमींदोज के तहत की गई है। बालोतरा पुलिस थाने के हिस्ट्रीशीटर अनवर खां के खिलाफ अलग-अलग व गंभीर धाराओं में बालोतरा, जोधपुर, जालोर, शेरगढ़ आदि जगहों पर कुल 27 मामले दर्ज है। उन्होंने बताया कि ऐसे अपराधियों को चिह्नित कर लिया गया है और यह कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। ऑपरेशन जमींदोज की कार्रवाई मंगलवार को दोपहर के समय शुरू की गई थी। पुलिस जाब्ते के साथ अलग-अलग विभागों की टीमें अचानक जोधपुर रोड सरस डेयरी के सामने वाली गली में पहुंची। एसपी ने बताया कि यहां बालोतरा के हिस्ट्रीशीटर अनवर खां पुत्र सुमार खां निवासी नीलम सिनेमा के पीछे बालोतरा की ओर से किए गए अतिक्रमण को नियमानुसार हटाया गया। साथ ही हिस्ट्रीशीटर की ओर से अवैध रूप से संचालित कपड़ा धुलाई की फैक्ट्री को मौके पर ही नगर परिषद टीम से सीज करवाया गया। डिस्कॉम विभाग टीम से अवैध फैक्ट्री में लाइट कनेक्शन को कटवाया गया। वन विभाग से समन्वय स्थापित कर मौके पर एकत्र अवैध लकड़ियां बरामद करवाई गई। आगामी समय में चिह्नित शेष अपराधियों के नियम विरुद्ध-सरकारी भूमि पर अतिक्रमण चरणबद्ध तरीके से हटाया जाना प्रस्तावित है।

ऑपरेशन जमींदोज की सूची तैयार है

एसपी ने बताया कि ऑपरेशन जमींदोज के तहत ऐसे आरोपियों की सूची तैयार की गई है। इसी क्रम में थाना बालोतरा के हिस्ट्रीशीटर अनवर खां का एक बड़ा भूखंड दूध डेयरी के सामने नुरानी मोहल्ला जाने वाली सड़क पर मिला। इस भूखंड की आड़ में सरकारी जमीन सड़क पर 08 गुना 30 फीट का अतिक्रमण किया हुआ था। इस पर अतिक्रमण को नियमानुसार हटाया गया। हिस्ट्रीशीटर की ओर से अवैध रूप से संचालित कपड़ा धुलाई की फैक्ट्री को सीज करवाया गया। डिस्कॉम टीम ने अवैध फैक्ट्री में बिजली कनेक्शन काटा। वहीं वन विभाग ने अवैध लकड़ियां बरामद की।

केंद्र ने की सरकारी कर्मचारियों के मौलिक अधिकार की रक्षा

लोकेन्द्र सिंह

कहना होगा कि वैसे तो इस प्रतिबंध का कोई औचित्य नहीं रह गया था लेकिन फिर भी केंद्र सरकार ने इसे हटाकर अच्छा ही किया। इससे आमजन के ध्यान में यह भी आया कि पूर्ववर्ती सरकारों ने किस प्रकार राष्ट्रीय विचारधारा के दबाने का प्रयास किया। आज जब संविधान और लोकतंत्र की रक्षा की बहस चल रही है, तब भी उन्हें ध्यान आएगा कि किन सरकारों ने संविधान की मूलभावना के विरुद्ध कार्य किया।

केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की गतिविधियों में सरकारी कर्मचारियों के शामिल होने पर लगे प्रतिबंध को हटाकर नागरिक स्वतंत्रता की ही नहीं मौलिक अधिकार की रक्षा की है। अब कर्मचारी संघ की गतिविधियों में सामान्य नागरिकों की भांति शामिल हो सकेंगे। निसंदेह, सरकार का यह निर्णय लोकतंत्र और संविधान की भावना को मजबूत करने वाला है। भारत का संविधान प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार देता है कि वह विविध सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक संगठनों में शामिल हो सके। एक सामान्य नागरिक की भांति यह अधिकार कर्मचारियों को भी प्राप्त है कि अपने कार्यालयीन समय के बाद सामाजिक गतिविधियों का हिस्सा हो सकते हैं। परंतु, लोकतंत्र और संविधान की मूल भावना को कमजोर करते हुए तत्कालीन सरकार ने 1966 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की गतिविधियों में सरकारी कर्मचारियों के भाग लेने पर प्रतिबंध लगा दिया था। इतना ही नहीं, सरकारी कर्मचारी के संघ की गतिविधियों में शामिल होने पर उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई का विधान भी रखा था। यह एक प्रकार से राष्ट्रीय विचार के प्रति झुकाव रखनेवाले लोगों को हतोत्साहित करने का प्रयास ही था।

इस तानाशाही एवं द्वेषपूर्ण निर्णय का उत्तर संघ ने तो कभी नहीं दिया लेकिन समाज ने अवश्य ही आईना दिखाने का कार्य किया। संघ को दबाने एवं समाप्त करने के लिए अनेक प्रयत्न किए हैं। इस आदेश के अतिरिक्त तीन बार पूर्ण प्रतिबंध भी लगाया। संघ की छवि खराब करने के लिए बड़े-बड़े नेताओं की ओर से मिथ्या प्रचार भी किया गया। अपने समर्थक बुद्धिजीवियों से पुस्तकें भी लिखवाई गईं। लेकिन संघ विरोधियों के ये सब प्रयास विफल ही रहे। निस्वार्थ भाव से देश और समाज के लिए कार्य करनेवाले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को कोई रोक नहीं सका। अपनी लंबी यात्रा में संघ ने लगातार प्रगति एवं विस्तार ही किया है। अपने विचार, आचरण एवं सेवाकार्यों से संघ ने समाज का विश्वास जीता, जिसके कारण समाज सदैव संघ के साथ खड़ा रहा।

कई ऐसे उदाहरण हैं, जिनमें संघ गतिविधि में शामिल होने पर सरकारों ने सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की। लेकिन वे सभी मामले न्यायालय में टिक नहीं सके। संघ के स्वयंसेवक न्यायालय से जीतकर आए। उनकी छोटी-छोटी जीतों की श्रृंखला ने भी यह साबित किया कि संघ की गतिविधियों में शामिल होने से रोकने के लिए लगाया गया तत्कालीन सरकार का आदेश संविधान एवं मौलिक अधिकारों की मूल भावना के विरुद्ध था। इस प्रतिबंध को 1966 के बाद से ही चुनौती मिलने लगी थी। क्योंकि संघकार्य को बाधित करने और स्वयंसेवकों को प्रताड़ित करने की जिस मंशा से सरकार ने यह प्रतिबंध लगाया था, उसे अंजाम देने का कार्य देशभर में शुरू किया गया। इस प्रतिबंध को हथियार बनाकर सरकारों ने देश के विभिन्न राज्यों में संघ से जुड़े कार्यकताओं की नौकरी

छीनना शुरू कर दिया। सरकार की मनमानी को स्वयंसेवकों ने न्यायालयों में चुनौती दी, जहां सरकारों को मुंह की खानी पड़ी। मैसूर उच्च न्यायालय ने वर्ष 1966 में रंगनाथचार अग्निहोत्री की याचिका पर निर्णय देते हुए कहा था कि प्रथम दृष्ट्या आरएसएस एक गैर-राजनैतिक एवं सांस्कृतिक संगठन है जो कि गैर-हिंदुओं के प्रति किसी भी द्वेष अथवा घृणा की भावना से मुक्त है। इसी क्रम मे न्यायालय ने आगे कहा कि संघ ने भारत में लोकतांत्रिक पद्धति को स्वीकार किया है। अतः राज्य सरकार द्वारा याची को सेवा से हटाने का निर्णय गलत है। इसके साथ ही न्यायालय ने उक्त कर्मचारी को सेवा में बहाल करने का निर्णय सुनाया। इसी प्रकार, वर्ष 1967 में पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार के कर्मचारी रामपाल को पद से हटाने संबंधी आदेश को रद्द करते हुए कहा कि संघ कोई राजनैतिक संगठन नहीं है, अतः इसकी गतिविधियों में भागीदारी करना कानूनी रूप से गलत नहीं है। ज्ञातव्य है कि राज्य सरकार द्वारा रामपाल को पद से इस आधार पर हटाया गया था कि वे संघ की गतिविधियों में भाग लेते हैं एवं राज्य की दृष्टि में संघ एक राजनैतिक संगठन है। भारत प्रसाद त्रिपाठी बनाम मध्य प्रदेश सरकार तथा अन्य प्रकरण में तो 1973 में मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय ने यहां तक कह दिया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के किसी कार्यक्रम में भाग लेने के आधार पर किसी कर्मचारी की सेवा समाप्त नहीं की जा सकती। किसी अंतरस्थ हेतु जारी किया गया (इस आशय का) कोई आदेश वैध नहीं ठहराया जा सकता। यानी न्यायालय ने संघ की गतिविधि में शामिल होने से रोकने के लिए लगाए गए किसी भी प्रतिबंध/आदेश को अवैध करार दिया। इसके अलावा 'मध्यप्रदेश राज्य बनाम राम शंकर रघुवंशी तथा अन्य (1983)', मामले में उच्च न्यायालय, 'श्रीमती थाट?टुमकर बनाम महाप्रबंधक टेलीकम्यूनिकेशन्स, केरल मंडल (1982)' मामले में अनार्कुलम स्थित केरल उच्च न्यायालय और 'डीबी गोहल बनाम जिला न्यायाधीश, भावनगर तथा अन्य (1970)' मामले में गुजरात उच्च न्यायालय ने यही निर्णय दिए कि संघ से जुड़े होने या उसके कार्यक्रमों में शामिल होने के आधार पर किसी कर्मचारी पर न तो कार्रवाई की जा सकती है और न ही उन्हें सेवा से हटाया जा सकता है।

कुछ प्रकरण ऐसे भी हैं, जिनमें संघ के कार्यकर्ताओं को इस प्रतिबंध के लागू होने से पहले ही निशाना बनाया गया। इन मामलों से स्पष्ट है कि तत्कालीन सरकारें शुरू से ही चाहती थीं कि संघ के कार्यक्रमों में शामिल होनेवाले लोगों के मन में भय उत्पन्न किया जाए। ताकि हिन्दुओं के संगठन के कार्य को रोका जा सके। परंतु, न्यायपालिका से लेकर आमजन की कसौटी पर राष्ट्रीय विचार को कमजोर करने के सभी प्रयास विफल रहे। 'कृष्ण लाल बनाम मध्यभारत राज्य (1955)' में इंदौर स्थित मध्य भारत उच्च न्यायालय, 'चिंतामणि नुरगांवकर बनाम पोस्ट मास्टर जनरल, कें.मं., नागपुर (1962)' में बंबई उच्च न्यायालय की नागपुर न्यायपीठ, 'जयकिशन महरोत्रा बनाम महालेखाकार (1963)' में इलाहाबाद उच्च न्यायालय, 'केदारलाल अग्रवाल बनाम राजस्थान राज्य तथा अन्य (1964)' मामले में जोधपुर स्थित राजस्थान उच्च न्यायालय और 'मनोहर अंबोकर बनाम भारत संघ तथा अन्य (1965)' प्रकरण में दिल्ली स्थित पंजाब उच्च न्यायालय ने यही कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ गैरकानूनी संगठन नहीं है। सरकारी कर्मचारी को संघ के कार्यक्रमों में भाग लेने के आधार पर दंडित नहीं किया जा सकता। यदि कोई सरकारी कर्मचारी संघ का सदस्य है तब भी उसे इस आधार पर अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त नहीं किया जा सकता। स्मरण रखें कि अंग्रेजों ने भी सरकारी कर्मचारियों के संघ से प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया था। अंग्रेजी हुकूमत की ओर से जारी परिपत्र में आदेश दिया गया कि 'सरकार ने निर्णय लिया है कि किसी भी सरकारी कर्मचारी को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सदस्य बनने अथवा उसके कार्यक्रमों में भाग लेने की अनुमति नहीं रहेगी'। कहा जा सकता है कि सरकारी कर्मचारियों को आरएसएस की गतिविधियों में भाग लेने से रोकने के लिए जिस प्रकार का प्रतिबंध कांग्रेस सरकार ने लगाया, वह औपनिवेशिक काल की अंग्रेजों की नीति को ही आगे बढ़ाने का कार्य था।

बाद के वर्षों में जब राज्यों में राष्ट्रीय विचार का पोषण करनेवाली सरकारें आईं तो उन्होंने लोकतंत्र एवं मौलिक अधिकार विरोधी इस प्रतिबंध को राज्यों में समाप्त कर दिया। संघ ने इस प्रतिबंध की कभी चिंता नहीं की क्योंकि न्यायालयों में इस तुगलकी फरमान के घुटने इतने अधिक छिल गए थे कि यह स्वतः ही निष्प्रभावी हो गया था। फिर भी, वर्ष 2000 में जब संघ के तत्कालीन सरसंघचालक प्रोफेसर राजेन्द्र सिंह उपाख्य रज्जू भैया से पूछा गया कि संघ इस प्रतिबंध को लेकर क्या सोचता है? तब उन्होंने कहा था कि संघ की गतिविधियों में सरकारी कर्मचारियों के भाग लेने पर प्रतिबंध लगाने अथवा हटाने की कार्यवाही में हम कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे, इसके निर्णय का अधिकार सरकारों के पास है। उल्लेखनीय है कि गुजरात सरकार ने इस दिशा में सबसे पहला कदम उठाया। बाद में उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश की सरकारों ने भी प्रतिबंध को हटा लिया। यह प्रतिबंध केवल केंद्र सरकार में रह गया था, उसे भी वर्तमान केंद्र सरकार ने संघ के हस्तक्षेप के बिना, स्वतः ही समीक्षा करने के बाद हटा लिया है। केंद्र सरकार के निर्णय पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से भी संतुलित टिप्पणी की गई है। अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर ने कहा- राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ गत 99 वर्षों से सतत राष्ट्र के पुनर्निर्माण एवं समाज की सेवा में संलग्न है। राष्ट्रीय सुरक्षा, एकता-अखंडता एवं प्राकृतिक आपदा के समय में समाज को साथ लेकर संघ के योगदान के चलते समय-समय पर देश के विभिन्न प्रकार के नेतृत्व ने संघ की भूमिका की प्रशंसा भी की है। अपने राजनीतिक स्वार्थों के चलते तत्कालीन सरकार द्वारा शासकीय कर्मचारियों को संघ जैसे रचनात्मक संगठन की गतिविधियों में भाग लेने के लिए निराधार ही प्रतिबंधित किया गया था। शासन का वर्तमान निर्णय समुचित है और भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को पुष्ट करने वाला है'। कहना होगा कि वैसे तो इस प्रतिबंध का कोई औचित्य नहीं रह गया था लेकिन फिर भी केंद्र सरकार ने इसे हटाकर अच्छा ही किया। इससे आमजन के ध्यान में यह भी आया कि पूर्ववर्ती सरकारों ने किस प्रकार राष्ट्रीय विचारधारा के दबाने का प्रयास किया। आज जब संविधान और लोकतंत्र की रक्षा की बहस चल रही है, तब भी उन्हें ध्यान आएगा कि किन सरकारों ने संविधान की मूलभावना के विरुद्ध कार्य किया।

(लेखक, स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं।)

संपादकीय

संतुलित बजट

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण का 2024 का बजट कई मामलों में संतुलित माना जाएगा। नरेन्द्र मोदी की अगुवाई में राजग सरकार के तीसरी बार सत्ता में आने के बाद यह पहला बजट है। बजट में निसंदेह मानव संसाधन विकास और बुनियादी विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है। केंद्र सरकार वेतनभोगियों की उम्मीदों में वह खरी उतरीं। नई टैक्स व्यवस्था में अब स्टैंड़र्ड.ड़िड़क्शन पचास हजार से बढ़ाकर पिच्छत्तर हजार रुपए कर दिया। वेतनभोगियों को इनकम टैक्स में 17,500 रुोपए तक की बचत होगी। वित्तमंत्री का कहना है कि इनकम टैक्स एक्ट की छह महीने में समीक्षा की जाएगी। कैपिटल गेन छूट की सीमा बढ़ा दी गई है। महिलाओं द्वारा खरीदी गई संपत्ति पर स्टॉम्प ड़्यूटी कम करने के साथ ही चुनिंदा शहरों में साप्ताहिक हाट या स्ट्रीट फूड़ हब डेव़लप करने की योजना भी है। सौ बड़े.शहरों के लिए जलापूर्ति, सीवेज उपचार व ठोस अपशिष्ट परियोजनाओं की भी घोषणा की। देश में घरेलू क्रूज का परिचालन करने वाली विदेशी शिपिंग कंपनियों के लिए सरल कर व्यवस्था दी। सरकार ने स्पेस इकोनॉमी के लिए हजार करोड़.रुपए के वेंचर कैपिटल फंड़ स्थापित करने का भी प्रस्ताव रखा। सोने-चांदी पर कस्टम ड़्यूटी घटाकर 6 फीसद व प्लैटनियम पर 6.5 फीसद का प्रस्ताव रखा। टीड़ीएस में देरी को अपराध से बाहर कर सीतारमण ने नौकरीपेशा को राहत दी है। केंद्रीय बजट में युवाओं के रोजगार के लिए 500 टॉप कंपनियों में एक करोड़.युवाओं को इंटर्नशिप मुहैया कराने के साथ ही पांच हजार रुोपए महीने स्टाइपेंड़ देने की भी बात की। बजट के जरिये सियासी समीकरण दुरुस्त करने और विपक्षी धार को कुंद करने की रणनीति के तहत सरकार ने अपने अहम सहयोगी दलों जेड़ी (यू) व टीड़ीपी शासित राज्यों बिहार व आंध्र प्रदेश के लिए विशेष पैकेज दिया। हालांकि इस दिलदारी से बाकी राज्यों में सरकार के खिलाफ आवाज तेज होगी। खैर, जैसी उम्मीदें थीं, बजट वैसा नहीं रहा। विपक्ष का आरोप है कि बजट में गरीबों व आम लोगों के लिए कुछ नहीं है। साथ ही इसे राजनीतिक पूर्वाग्रह से ग्रसित भी बताया।

चिंतन-मनन

उपयोगी हल

एक बार की बात है एक राजा था। उसका एक बड़ा-सा राज्य था।एक दिन उसे देश घूमने का विचार आया और उसने देश भ्रमण की योजना बनाई और घूमने निकल पड़ा। जब वह यात्रा से लौट कर अपने महल आया। उसने अपने मंत्रियों से पैरों में दर्द होने की शिकायत की। राजा का कहना था कि मार्ग में जो कंकड़ पत्थर थे वे मेरे पैरों में चुभ गए और इसके लिए कुछ इंतजाम करना चाहिए। कुछ देर विचार करने के बाद उसने अपने सैनिकों व मंत्रियों को आदेश दिया कि देश की संपूर्ण सड़कें चमड़े से ढंक दी जाएं। राजा का ऐसा आदेश सुनकर सब सकते में आ गए। लेकिन किसी ने भी मना करने की हिम्मत नहीं दिखाई। यह तो निश्चित ही था कि इस काम के लिए बहुत सारे रुपए की जरूरत थी। लेकिन फिर भी किसी ने कुछ नहीं कहा। कुछ देर बाद राजा के एक बुद्धिमान मंत्री ने एक युक्ति निकाली।

उसने राजा के पास जाकर डरते हुए कहा कि मैं आपको एक सुझाव देना चाहता हूँ। अगर आप इतने रुपयों को अनावश्यक रूप से बर्बाद न करना चाहें तो एक अच्छी तरकीब मेरे पास है। जिससे आपका काम भी हो जाएगा और अनावश्यक रुपयों की बबार्दी भी बच जाएगी। राजा आश्चर्यचकित था क्योंकि पहली बार किसी ने उसकी आज्ञा न मानने की बात कही थी। उसने कहा बताओ क्या सुझाव है। मंत्री ने कहा कि पूरे देश की सड़कों को चमड़े से ढंकने के बजाय आप चमड़े के एक टुकड़े का उपयोग कर अपने पैरों को ही क्यों नहीं ढंक लेते। राजा ने अचरज की दृष्टि से मंत्री को देखा और उसके सुझाव को मानते हुए अपने लिए जूता बनवाने का आदेश दे दिया। यह कहानी हमें एक महत्वपूर्ण पाठ सिखाती है कि हमेशा ऐसे हल के बारे में सोचना चाहिए जो ज्यादा उपयोगी हो। जल्दबाजी में अप्रायोगिक हल सोचना बुद्धिमानी नहीं है। दूसरों के साथ बातचीत से भी अच्छे हल निकाले जा सकते हैं।

राष्ट्रपति चुनाव से वाइडेन हटे, ट्रंप को भारतवंशी कमला हैरिस से मिलेगी कड़ी टक्कर

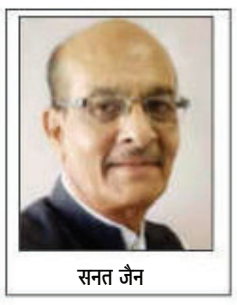

सनत जैन

राष्ट्रपति पद के चुनाव से हटने की घोषणा वर्तमान राष्ट्रपति जो वाइडेन ने कर दी है। वाइडेन ने उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को राष्ट्रपति पद के लिए समर्थन दिया है। डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से कमला हैरिस राष्ट्रपति पद के लिए सबसे प्रबल दावेदार थी। पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा, डेमोक्रेटिक पार्टी के किंग मेकर बनकर उभरे हैं। उन्होंने वाइडेन को राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ने की सलाह दी थी। पूर्व विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन ने भी वाइडेन के राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी से हटने के बाद,कमला हैरिस को समर्थन देने की घोषणा कर दी है। 19 अगस्त को शिकागो में डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन की बैठक होगी। जिसमें 4000 से अधिक डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रतिनिधि शामिल होंगे। पार्टी की ओर से राष्ट्रपति पद के लिए अधिकृत नाम की घोषणा शिकागो कन्वेंशन मे होगी। कमला हैरिस की उम्मीदवारी पर डेमोक्रेटिक पार्टी का कोई चुनौती देना चाहेगा। तो उसे 600 प्रतिनिधियों का समर्थन प्राप्त करके उम्मीदवारी का दावा करना होगा। राष्ट्रपति पद के चुनाव मे लगभग 105 दिन बाकी हैं। जिस तेजी के साथ अमेरिका में राजनीतिक हालात बदल रहे हैं। उसको लेकर यह कहा जा रहा है, जो वाइडेन के चुनाव मैदान से हटने के बाद पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए मुसीबतें बढ़ेंगी। डोनाल्ड ट्रंप के सामने जो वाइडेन कमजोर साबित हो रहे थे। पिछले वर्षों में उपराष्ट्रपति के रूप में कमला हैरिस ने अपने कामकाज को लेकर अमेरिका में सभी वर्गों में लोकप्रियता हासिल की है। कमला हैरिस भारतवंशी है। डोनाल्ड ट्रंप ने उपराष्ट्रपति पद के लिए भारतवंशी महिला के पति को अपना उम्मीदवार बनाया है। भारतीय मूल के और अश्वेत वर्ग के लोगों में कमला हैरिस को काफी गंभीरता से लिया जाता है। वह एक सूझबूझ वाली महिला हैं। राष्ट्रपति पद के चुनाव में पिछले एक माह में जिस तरह के परिवर्तन अमेरिका में देखने को मिल रहे हैं। उससे लग रहा है, अमेरिका नया इतिहास बनाने जा रहा है। पूर्व विदेश मंत्री हेलरी क्लिंटन ने राष्ट्रपति पद का चुनाव 2016 में लड़ा था। उन्हें डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव हराया था। अमेरिका के इतिहास में अभी तक कोई महिला राष्ट्रपति नहीं हुई है। अमेरिका में दूसरी बार महिला, राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय मूल के लोगों का समर्थन पाने के लिए पिछले चुनाव के पहिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ राष्ट्रपति रहते हुए अच्छे संबंध बनाए थे। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछली बार अमेरिका में अबकी बार ट्रंप सरकार के नारे लगाए थे। उसके बाद भी ट्रंप पिछला चुनाव हार गए थे। कमला हैरिस के चुनाव मैदान में आने के बाद, राष्ट्रपति चुनाव के सारे समीकरण बदल गए हैं। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ कई मामले अदालत में लंबित है। कुछ मामलों में उन्हें सजा हो चुकी है। अमेरिका में वह कट्टरबाद के सहारे अपनी राजनीति को आगे बढ़ा रहे हैं। जिस तरह से दुनिया के देशों में दक्षिणपंथी विचारधारा कमजोर हो रही है। ऐसी स्थिति में कमला हैरिस, राष्ट्रपति पद के चुनाव में ट्रम्प को कड़ी चुनौती देंगी। ट्रम्प को जो समर्थन वाइडेन के कारण अभी मिल रहा था। निश्चित रूप से अब कमला हेरिस से उन्हें चुनौती मिलना तय है। ट्रम्प की लोकप्रियता में भी गिरावट देखने को मिल सकती है। पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा और पूर्व विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन का समर्थन कमला हैरिस को मिल रहा है। भारतीय मूल के नागरिकों का समर्थन भी कमला हैरिस को बड़े पैमाने पर मिलना तय माना जा रहा है। जो वाइडेन के चुनाव मैदान से हट जाने के बाद, अमेरिका की राजनीति में बड़ा बदलाव आ गया है। जो वाइडेन के सामने ट्रंप काफी मजबूत थे। जिस तरह से चुनाव के बीच जो वाइडेन ने अपनी उम्मीदवारी वापस ली है।

मुद्दा: क्यों सरदार पटेल की सीख से पूजा खेडकर दूर रही

आर.के. सिन्हा

लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल ने 21 अप्रैल, 1947 को राजधानी के मेटकॉफ हाउस में आजाद होने जा रहे भारत के पहले बैच के आई सी एस जो 1948 से आई पी जो 1948 से आई पी एस कहलाये ऐसे सभी अफसरों को संबोधित करते हुए कहा था कि 'उन्हें स्वतंत्र भारत में जनता के सवालों को लेकर गंभीरता और सहानुभूति का भाव रखना होगा। उन्हें अपने दायित्वों का निर्वाह ईमानदारी से करना होगा। ' सरदार पटेल ने उन्हें स्वराज और सुराज का अंतर भी समझाया था। जाहिर है, उनका ईमानदारी से आशय यही रहा होगा कि वे अपने जीवन के हर क्षेत्र में शुचिता और तटस्थता का पालन करेंगे। पर हाल में आईएएस प्रोबेशनर, पूजा खेडकर मामले को गहराई से देखने से समझ आ रहा है कि कुछ शातिर तत्व आईएएस या अन्य सरकारी नौकरियों को पाने के लिए फर्जी प्रमाणपत्र भी सौंपते हैं। उनके लिए ईमानदारी का कोई मतलब नहीं है। उन्हें सरदार पटले की सीख से भी कोई लेना-देना नहीं।

पूजा खेडकर मसूरी के लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में प्रशिक्षण ले रही थीं। उन्हें महाराष्ट्र, शायद उनके अपने राज्य कैडर, में जिला प्रशिक्षण के लिए भेजा गया था। उन्हें एहसास नहीं था कि आईएएस अफसर बनने का मतलब जन सेवा होता है। इसके बजाय, उसने इस पद को हासिल करने के बाद अपनी झूठी शान दिखानी शुरू कर दी। उसने कार, सुसज्जित कार्यालय और कर्मचारियों जैसी कई सुविधाओं की मांग की। चूँकि प्रोबेशनर्स इन लाभों के हकदार नहीं होते हैं, इसलिए उन्हें कोई भी लाभ नहीं दिया गया। इसलिए, उसने अपनी दैनिक जरूरतों के लिए एक लग्जरी कार 'किराए पर' ली। इससे भी बुरा यह है कि उन्होंने कार की छत पर नीली बीकन लाइट भी लगाई। बीकन लाइट के इस्तेमाल को लेकर नियम हैं कि हर कोई ऐसी लाइट नहीं लगा सकता, जिसके कार्यात्मक उद्देश्य आवश्यक नहीं हैं। एम्बुलेंस वाहन पर ऐसी लाइट वाहन की तेज गति को सुविधाजनक बनाने के लिए है।

पूजा का चयन दो विशेष श्रेणियों के तहत किया गया था। एक, वह ओबीसी के गैर-क्रीमी वर्ग से संबंधित हैं। यह स्वयं ही संदिग्ध है, यह देखते हुए कि उनके पिता एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी थे। फिर वह गैर-क्रीमी लेयर में कैसे चुनी गई। वह निश्चित रूप से गरीब व्यक्ति नहीं थी। उनके परिवार के पास पर्याप्त जमीन है जो निश्चित रूप से उन्हें एक अलग आर्थिक श्रेणी में रखेगी। पूजा ने यह भी दावा किया था कि उसकी एक अलग तरह की शारीरिक स्थिति है, जो उसे विकलांग कोटे के तहत आरक्षित सीट के लिये हकदार बनाती है। यूपीएससी और कार्मिक विभाग द्वारा विकलांगता के संबंध में कुछ तय दिशानिदेर्शों का पालन करते हैं। एक व्यक्ति जिसे एक आंख में दृष्टि नहीं होती है, उसे 'विकलांग' नहीं माना जाता है, यदि दूसरी आंख हर तरह से ठीक है।

मैंने इसके बारे में तब जाना जब मेरे एक मित्र के पुत्र ने सिविल सेवा परीक्षा दी। । बचपन में, उसके एक भाई ने उसकी दाहिनी आंख में कंपास डाल दिया था, जिससे वह आंशिक रूप से अंधा हो गया था। वह विकलांग कोटे के तहत आरक्षण के लिए योग्य नहीं होता, अगर उसकी दूसरी आंख सही होती। उसकी ₹सामान्य₹ आंख में आंशिक अंधापन था। इस तरह वह रेलवे सेवा के लिए चुना गया, जहाँ वह अब एक जिम्मेदार पद पर है।

पूजा खेडकर के मामले में, वह लोकोमोटर डिफिशिएंसी का दावा करती है, जो उसकी बाहों और पैरों के चलने में बाधा उत्पन्न करती है। डॉक्टर और तकनीशियन आसानी से कमी का आकलन कर सकते हैं। उसे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के मेडिकल बोर्ड के सामने खुद को प्रस्तुत करना चाहिए था, जो यह प्रमाणित करता था कि वह विकलांग श्रेणी में शामिल करने के लिए योग्य है या नहीं।

किसी न किसी बहाने से, वह बोर्ड के सामने पेश नहीं हुई, एक बार नहीं बल्कि पांच बार। वह उन अस्पतालों से विकलांगता का उचित प्रमाण पत्र भी प्राप्त नहीं कर सकी थी जिनसे उसने कथित तौर पर संपर्क किया था। यह भी रिकॉर्ड पर है कि उसने 2007 में एक मेडिकल कॉलेज में शामिल होने के दौरान पूर्ण फिटनेस प्रमाण पत्र जमा किया था। उल्लेखनीय बात यह है कि कार्मिक विभाग ने उसे मसूरी में आवश्यक प्रशिक्षण प्राप्त करने और मेडिकल चेक-अप पास किए बिना आईएएस में शामिल होने की अनुमति दी। यहाँ कोई गंभीर गलती हुई है, जो भ्रष्टाचार की श्रेणी में आयेगा और सही और निष्पक्ष जांच के बाद इसके लिये दोषी अधिकारी या अधिकारीयों को दण्डित तो करना ही होगा।

केंद्र सरकार ने एक मेडिकल परीक्षा का आदेश दिया है जिसके लिए उसने एक व्यक्तिगत समिति नियुक्त की है, जो यह साबित करेगी कि क्या वह किसी भी विकलांगता से पीड़ित है। अगर उसने नखरे नहीं दिखाए होते, तो वह सेवा में बनी रहती। इससे कांड के बाद यूपीएससी की कार्यप्रणाली भी अच्छी रोशनी में नहीं दिखता है।

इससे भी गंभीर बात यह है कि पूजा अपने जिला मजिस्ट्रेट जिससे अधीन वह प्रशिक्षण प्राप्त ककर रही थी उनके आदेशों की अनदेखी करती थी। यह सरकारी सेवा में एक गंभीर आरोप है। इस बीच, तेलंगाना में एक आईएएस अधिकारी के बारे में भी रिपोर्ट आई हैं, जो कुछ विकलांगताओं के आधार पर सेवा में शामिल हुए। उदाहरण के लिए, उन्हें कथित तौर पर पोलियो का हमला हुआ है। लेकिन घोड़े की सवारी और साइकिल चलाते हुए उनके वीडियो यह तो नहीं बताते कि वे कभी पोलियो के शिकार थे?। इससे यह सवाल उठता है कि क्या सिविल सेवाओं में विकलांग श्रेणियों के तहत रिक्तियों को भरने में मानदंडों का सख्ती से पालन किया जाता है। लगता तो यही है कि इस मामले में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है और पिछले दस-पंद्रह साल में विकलांगता के आधार पर चुने गये ऐसे सभी मामलों को जांच के दायरे में लाने की आवश्यकता है।

आईएएस, जिसे अक्सर ₹भारत के इस्पात फ्रेम₹ के रूप में जाना जाता है, यह उपाधि सरदार वल्लभभाई पटेल, 'भारत के लौह पुरुष' से प्राप्त करता है। उन्होंने नव स्वतंत्र भारत की एकता और स्थिरता बनाए रखने में सिविल सेवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर देने के लिए इस शब्द का इस्तेमाल किया था। आईएएस राष्ट्र के प्रभावी शासन के लिए आवश्यक, सबसे प्रतिष्ठित सेवाओं में से एक है। इस सेवा में भर्ती में कोई भी समझौता देश के हितों को गंभीर रूप से कमजोर कर सकता है। यदि देश की जनता के दिल में आईएएस पदाधिकारियों के प्रति स्वाभाविक रूप से सम्मान और आदर का भाव नहीं रह जायेगा, तो कोई भी आईएएस प्रशासन कर ही नहीं पायेगा।

आईएएस अधिकारियों से अपनी भूमिकाओं में निष्पक्षता और अखंडता का प्रदर्शन करने की अपेक्षा की जाती है। उनके फैसले लाखों लोगों के जीवन और देश की समग्र स्थिरता को प्रभावित करते हैं। निष्पक्षता बनाए रखकर और कानून के शासन का पालन कर-के, आईएएस अधिकारी यह सुनिश्चित करने में मदद करते हैं कि सरकार की नीतियां और कार्यक्रम निष्पक्ष रूप से और प्रभावी ढंग से लागू किए जा रहे हैं। भर्ती प्रक्रिया से समझौता पक्षपात ला सकता है और कानून के शासन को कमजोर कर सकता है, जिससे अस्थिरता और जनता का विश्वास कम हो सकता है। पूजा खेड़कर का मामला इस बात की गवाही है कि हमारे देश में फर्जी प्रमाणपत्र दिखाकर मलाई खाने का खेल खूब चल रहा है, जिसे तत्काल बंद किये जाने की आवश्यकता है।

(लेखक वरिष्ठ संपादक, स्तंभकार और पूर्व सांसद हैं)

शिवगंज नगर पालिका अधिकारी व पालिकाध्यक्ष की मिली भक्ति से फर्जी पट्टे बनाकर देने पर लोकायुक्त मे प्रकरण दर्ज

पालडी जोड रोड पर आर्यावर्त कोलोनी मालिक व पालिका प्रशासन ने मिलकर फजीर्वाडा किया है

50 हजार का प्लाट बेचा 6 लाख 50 हजार मे सरकार व गरीबों के पेट पर लात मारी

करोडों कमाई के चक्कर मे गरीबों के के भूखंड अमीरों को बेंचा गया

द पुलिस पोस्ट

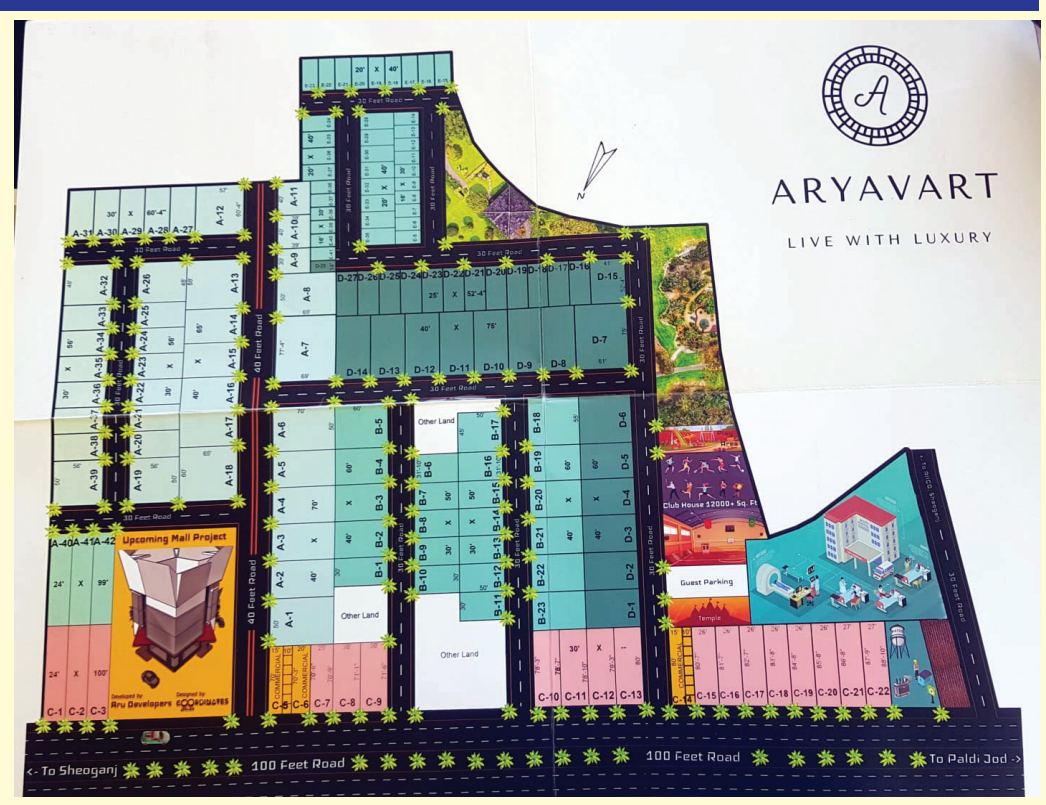

क्र.सं.	भू–उपयोग	क्षेत्रफल (वर्गफीट)	प्रतिशत	योजना में कुल प्रतिशत
1.	आवासीय	245970.08	90.95	50.65
	EWS/LIG हेतु	24480.00	09.05	
	कुल आवासीय भूमि	270450.08		
2.	व्यावसायिक	28272.53	05.29	05.29
	इन्फॉर्मल	3757.41	00.70	00.70
3.	पार्क	29913.00	05.60	05.60
4.	अन्य सामुदायिक सुविधा हेतु	53349.10	10.00	10.00
5.	सड़क	148214.79	27.76	27.76
	कुल क्षेत्रफल	533957.00	100.00	100.00

शिवगंज नगर पालिका में गरीबों के भुखंड अमीरों को बांटे जा रहे हैं मकान शिवगंज नगर पालिका क्षेत्र के अखापुरा ग्रामीण क्षेत्र में एक आर्यव्रत कॉलोनी जो की 32 बीघा से अधिक थी उसमें 9% ईडब्ल्यूएस एल आई जी के भुखंड गरीबों के लिए आरक्षित होते हैं उन भूखडो को कॉलोनी मालिक द्वारा यहां के भूमाफियाओ के साथ मिलकर वहां पर बंगले बनाकर बेचे जा रहे हैं ईडब्ल्यूएस एल आई जी के भुखंड की जगह पर कुछ दिन पहले मुहूर्त किया मुहूर्त कर वहां पर बंगले बनाने की तैयारी पूर्ण कर दी नगर पालिका द्वारा यह पट्टे लॉटरी द्वारा आवंटन होते हैं पर पालिका ने लॉटरी की कोई प्रक्रिया नहीं करके सीधे ही अमीरों को बेचने में लग गए और एक मकान की कीमत 18 लाख और 25 लॉख रुपए रखी गई है क्योंकि यह पट्टा इनको फोकट में ही मिलता है और कुछ निर्माण करके बड़ी रकम कमाने के फिराक में है क्योंकि जब यह ईडब्ल्यूएस एल आई जी के भुखंड छोड़े जाते है तो टाउन पॉलिसी के नियमों अनुसार नियम है यह भूकंप सभी गरीब परिवारों एससी एसटी को आवंटन किया जाए पर इन लोगों ने कोई प्रक्रिया नहीं करके सीधे ही कॉलोनी मालिक को पट्टे जारी कर दिए जो नियम विरुद्ध है यह कॉलोनी शिवगंज से पालडी जोड़ वाले रास्ते पर हैं इस कॉलोनी में और भी फर्जी वाडा खूब हुए क्योंकि फैसिलिटी की जमीन पूरी कॉलोनी वालों के लिए आरक्षित होती है पर इस कॉलोनी मालिक ने धन देकर सिर्फ अपनी निजी अस्पताल बनाने के लिए वह पैसा कमाने के लिए एक निजी अस्पताल बनाकर लोगों से पैसा वसूल करेंगे यह जमीन तो पूरी कॉलोनी के निवास करने वाले लोगों के लिए आरक्षित थी और इसमें कुछ उल्टा सीधा कर ऊपर वालों को पैसा खिलाकर अस्पताल के लिए आरक्षित करवा दी जो नियम विरुद्ध है इस कॉलोनी का किनारा वहां पर एक बड़ा सर्किल है मास्टर प्लान के अनुसार है उस सर्कल के हिसाब से 15 मीटर उसका रेडिएशन होता है जो इसकी कुछ भाग जमीन इसमें जाती है पर पालिका कर्मचारियों अधिकारियों की साठ गांठ कर के सब उल्टा काम कर इस कॉलोनी मालिक ने पैसा फेंक कर यह सब काम करवाए जा रहे हैं इस कॉलोनी के निर्माण चालू है नहीं तो उसमें कोई साइड बैक छोड़ा गया है और नहीं किसी प्रकार का नियम अनुसार कार्य हो रहा है आगे जो यह बंगले बना रहे हैं उसमें भी साइड बैक नहीं छोड़ा गया है और पालिका ने इसकी स्वीकृति जारी कर दी है जो एक बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है या नेताओं को अधिकारियों को इसमें प्लॉट या बांग्ला देकर खुश किया गया है इसलिए इस कॉलोनी मलिक को फर्जी निर्माण स्वीकृति वह ईडब्ल्यूएस एल आई जी के भुखंड के पट्टे जारी कर दिए इसने आगे वाणिज्य दुकान बनाई पीछे मकान बनाएं उसमें भी साइड बैक नहीं छोड़ा गया क्योंकि पालीका प्रशासन इस पर मेहरबान है इसलिए कोई नियम पालन नहीं हो रही है और फर्जी वाडे में सभी काम चालू है इस कॉलोनी मलिक ने अभी तक सड़के नहीं बनाई नहीं पानी के लाइन डाली

है और नहीं कोई विद्युत लाइन या नाली बनाई है उसके बाद भी इसको ईडब्ल्यूएस एलआईजी के भुखंडो के पट्टे भी जारी कर दिए इनको क्या पालिका प्रशासन इतने ईमानदार है की जल्दी में इस कॉलोनी मलिक को पट्टे जारी कर दिए क्योंकि इसमें नियमों की पालना हुई नहीं है फिर यह बंगले और प्लॉट लेने वाले पैसा देकर फिर रोएंगे और कॉलोनी मालिक तो पैसा लेकर चले जाएंगे तुरंत इन निमार्णों को रोका जाए वह पालिका प्रशासन के विरुद्ध कार्रवाई करावे शहर के जनप्रतिनिधि क्या कहती है शिवगंज नगर पालिका क्षेत्र के अखापूरा खूनी के आर्यावर्त कॉलोनी जिसमें ई डब्ल्यू एस एल

आई जी के भुखंडो की लॉटरी प्रक्रिया के अनुसार गरीबों को बांटे जाने थे पर पालिका प्रशासन ने कॉलोनी मालिक से सेंटिग कर सीधे ही कॉलोनी मलिक को दे दिए और उसमें बंगले बनाकर बड़ी रकम कमाने के फिराक में है 50 हजार का भूखंड 6 लॉख 50 हजार मे बेंचा गया जो सरकार व गरीबों के साथ धोखाधड़ी की है जो लोगों के साथ बड़ा धोखा है जैसाराम माली पूर्व पार्षद नगर पालिका शिवगंज

शिवगंज से पालड़ी जोड सड़क पर बड़ी कॉलोनी आर्यावर्त कोलोनी में ई डब्ल्यू एस एल आई जी के भुखंड जो टाउन पॉलिसी के नियमों के तहत आवंटन नहीं किए गए यह गरीबों के हित के पट्टे थे और इसमें फैसिलिटी की जमीन पर अस्पताल बनाकर लोगों के लूटने के प्रयास में कॉलोनी मालिक हैं इसलिए पालिका को यह दोनों खारिज कर वापस नियम अनुसार कार्रवाई करें अन्यथा हमें न्यायालय का सहारा लेना पड़ेगा

मुख्यमंत्री जनआवास योजनाओं में घपले रोकने की कवायद, यूडीएच विभाग ने जारी किए आदेश

EWS, LIG आवेदन के स्थानीय निवासी को मिलेगी प्राथमिकता, ग्रुप में आवेदन नहीं ले सकेंगे डवलपर्स

मुख्यमंत्री जन आवास योजना-2015 के नियम सख्त किए, कई योजनाओं में अनियमितता की शिकायतें मिल रही थीं

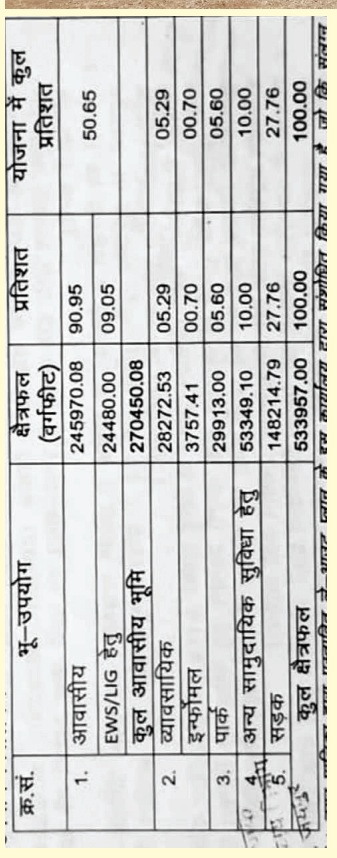

जयपुर| मुख्यमंत्री जन आवास योजनाओं में घपले घोटाले रोकने के लिए यूडीएच विभाग ने नियमों में सख्ती की है। विभाग को मुख्यमंत्री जन आवास योजना-2015 के प्रोविजन-1 में ईडब्ल्यूएस, एलआईजी कैटेगरी के भूखण्ड, फ्लैट आवंटन में अनियमितता की शिकायतें मिलने के बाद स्पष्ट गाइडलाइन जारी की है।

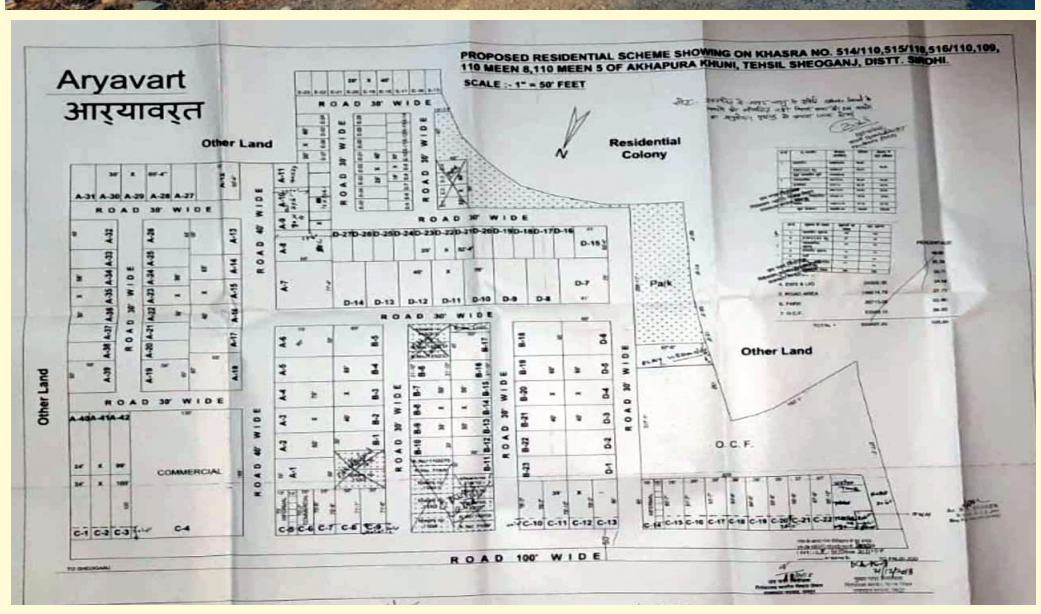

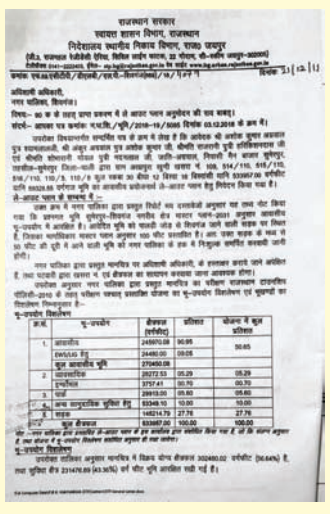

इस योजना में प्रोजेक्ट डवलपर छूट का फायदा लेकर आर्थिक रूप से पिछड़ों के लिए रिजर्व भूखंड और फ्लैट्स के आवंटन में घोटाला कर रहे थे। अब मुख्यमंत्री जन आवास योजना में ईडब्ल्यूएस, एलआईजी आवंटन के लिए लॉटरी में स्थानीय मूल निवासी को ही प्राथमिकता दी जाएगी। प्रोजेक्ट डवलपर फ्लैट्स स्कीम में 5, भूखंड स्कीम में 10 फीसदी जमीन ईडब्ल्यूएस, एलआईजी कैटेगरी के लिए चिन्हित कर लॉटरी से भूखण्ड आवंटित करने प्रावधान है। लॉटरी संबंधी गाइडलाइन स्पष्ट नही होने से कई बिचौलिए दूसरे जिलों और अन्य राज्यों के लोगों से आवेदन करवाकर गड़बड़ी करने की शिकायतें मिली थी। इससे स्थानीय आवासहीन लोगों को भूखण्ड आवंटन नहीं हो पाते। इसके अलावा कई प्रोजेक्ट डवलपर खुद का लॉटरी सॉफ्टवेयर या ऑफलाइन आवेदन लेकर आवंटन में गड़बड़ी कर रहे थे। 6 अक्टूबर को यूडीएच की मीटिंग में ये गाइडलाइन जारी करने का निर्णय हुआ था।

अब इन नियमों की पालना जरूरी

- लॉटरी में जिस जिले में प्रोजेक्ट है उसी जिले के निवासी और जिले में कार्यरत व्यक्तियों को ही आवेदन करने के लिए प्राथमिकता दी जाएगी। यदि ऐसे आवेदन प्राप्त नहीं होते है तो दूसरे जिलो से आवेदन लेकर लॉटरी निकाली जाएगी।
- आवेदन के लिए ईडब्ल्यूएस के लिए 10 और एलआईजी कैटेगरी में 20 हजार रुपए है। लॉटरी में सफल होने पर बिना ब्याज आवास की कीमत में समायोजित यह राशि समायोजित की जाएगी। इस राशि को डीडी के माध्यम से ले सकेंगे और 30 दिन में लॉटरी निकालना जरूरी होगा। लॉटरी में असफल आवेदकों को डीडी तत्काल लौटानी होगी।
- ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आवेदन के लिए वार्षिक आय 3 लाख, एलआईजी में 6 लाख और एमआईजी-ए में 12.0 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- डवलपर को ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 30 से 45 वर्गमीटर तक का भूखण्ड व 300-325 वर्ग फुट का आवास (फ्लेट), एलआईजी के लिए 45 से अधिक एवं 75 वर्गमीटर तक का भूखण्ड व 500-550 वर्गफुट का आवास (फ्लेट) और एमआईजी के लिए 75 व.मी. से अधिक 120 वर्ग मीटर तक भूखण्ड व न्यूनतम 750 वर्ग फुट क्षेत्रफल रखना अनिवार्य है। इन नियमों की पालना नहीं होने पर डवलपर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
- योजना में ईडब्ल्यूएस, एलआईजी कैटेगरी में ग्रुप में आवेदन नहीं लिए जा सकेंगे।

आईआईएम मुंबई
भारतीय प्रबंधन संस्थान मुंबई
(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार)

तब जाकर गरीब जनता के साथ न्याय होगा कमलसिंह चौहान समाजसेवी एवं गौ रक्षक शिवगंज

शिवगंज नगर पालिका मे जितनी भी बडी जमीन पर कोलोनीया काटी है वहाँ पर दो या चार टुकडे कर गरीबों के हित के भूखंड ई डब्लयू एस एल आई जी के भुखंड को सीधा बेचा जा रहा है गरीबों के साथ सब लोग व प्रशासन धोखाधड़ी कर रहे हैं सरकारी भूखंड को छह लॉख कमाई कर के व अधिकारीयों को कूछ धन देकर उल्टा सीधा कार्य कर रहे हैं जो अब कब कारवाई होगी गरीबों को भूखंड मिलेंगे सीमादेवी माली पार्षद नगर पालिका शिवगंज

प्रशासन की कार्रवाई : वन विभाग की भूमि पर अवैध निर्माण करने वालों को 7 दिन में अतिक्रमण हटाने का नोटिस जारी

भरतपुर। डीग जिले में साइबर ठगी के पैसे से सरकारी संपत्ति पर किए गए निर्माण को पुलिस व प्रशासन के द्वारा ध्वस्त करने की कार्रवाई की जा रही है। प्रशासन की कार्रवाई के चलते साइबर ठगो में हड़कंप मचा हुआ है। अवैध निर्माण का नोटिस मिलने के बाद डीग के रूंध खोह में साइबर ठग अब मकान को खुद ही तोड़ने लग गए हैं।

पुलिस का स्लोगन आमजन में विश्वास और अपराधियों में डर कारगर साबित हो रहा है। अपराधी पूरे तरीके से भयभीत नजर आ रहे हैं। डीग जिला कलेक्टर श्रुति भारद्वाज ने जिले के सभी एसडीएमओ को निर्देश दिए थे की पुलिस से साइबर ठगों की सूची प्राप्त कर अवैध संपत्ति को चिन्हित करते हुए कार्रवाई की जाए।

राजस्व विभाग एवं वन विभाग के द्वारा साइबर ठगों के अवैध निर्माण को चिन्हित कर उन पर पीला पंजा चलाया जा रहा है। पूर्व में पुलिस और प्रशासन के भारतपुर आईजी राहुल प्रकाश के ऑपरेशन एंटीवायरस अभियान के अंतर्गत सीकरी कैथवाड़ा और कामां में साइबर ठगों के मकानों को ध्वस्त कर चुके हैं। वन विभाग के क्षेत्रीय अधिकारी देवेंद्र सिंह ने बताया कि बारिस पुत्र हमीद मेंव निवासी रूंध खोह थाना खोह ने रूंध खोह में वन संरक्षित क्षेत्र की भूमि पर

अवैध अतिक्रमण कर पक्का मकान बना रखा है।

विभाग द्धारा 16 जुलाई को वारिस पुत्र हमीद मेव को नोटिस जारी कर 7 दिवस में वन विभाग की भूमि से अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए थे। साथ ही चेतावनी भी दी गई थी अगर स्वेच्छा से अवैध निर्माण को 24 जुलाई तक नहीं हटाया गया तो प्रशासन के द्वारा पीला पंजा चलाकर कार्रवाई की जाएगी। वारिस मेव के पिता हमीद एवं अन्य परिजनों ने स्वेच्छा से वन विभाग की भूमि से अपना अतिक्रमण हटाना शुरू कर दिया गया। गांव रूंध खोह निवासी 5 हजार के इनामी साइबर ठग को ठगी के मामले में 1 जुलाई को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। आरोपी को अभी जमानत नहीं मिली जो वर्तमान में कारागार डीग में विचाराधीन बंदी के रूप में बंदी है। कलेक्टर की सख्ती के बाद चिन्हित होने लगे अवैध निर्माण.. साइबर ठगों की अवैध संपत्ति को चिह्नित करने के लिए पुलिस को काफी परेशानी आ रही थी। वन विभाग एवं राजस्व विभाग पुलिस को सहयोग नहीं कर रहा था।

इधर, एसपी राजेश मीणा ने बताया कि ऑपरेशन एंटीवायरस का उद्देश्य था अपराधी अपराध को छोड़कर अवैध संपत्तियों को अतिक्रमण मुक्त कर दे, अपराधी स्वयं ही अपने अवैध निर्माण को हटाने लग गए हैं। पुलिस का स्लोगन कारगर साबित हो रहा है आमजन में विश्वास स्थापित हो रहा है तथा अपराधी भयभीत हैं।

नोखा में भामसं का 70वां स्थापना दिवस मनाया

प्रांतीय संगठन मंत्री बोले- राष्ट्र हित, उद्योग हित और श्रमिक हित की बात करता है बीएमएस

नोखा। जोधपुर डिस्कॉम श्रमिक बीएमएस के तत्वावधान में नोखा में आरएसईसीबी कॉलोनी में भारतीय मजदूर संघ का 70वां स्थापना दिवस मनाया गया। समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के जिला कार्यवाह लिखमाराम ने भामसं के संस्थापक और राष्ट्र ऋषि दतोपन्त ठेंगड़ी के जीवन के बारे में बताया।

अध्यक्षता श्रमिक संघ के पूर्व जिलाध्यक्ष भंवरसिह बीदावत ने की। जोधपुर डिस्कॉम श्रमिक संघ के प्रांतीय संगठन मंत्री चुन्नीलाल राजस्थानी ने बीएमएस की रीति नीति के बारे में बताते हुए कहा कि बीएमएस राष्ट्र हित, उद्योग हित और श्रमिक हित की बात करता है, राष्ट्र को प्रथम पंक्ति में रखता है। जिसकी बदौलत विश्व का नम्बर वन श्रम संगठन बना है। इस अवसर पर डिस्कॉम उपाध्यक्ष प्रेमसुख बिश्नोई, जिला भामसं के नरेंद्र छीपा, पूर्व जिला संरक्षक ओमप्रकाश रांकावत, पूर्व संगठन मंत्री शिवपालसिंह शेखावत, महेश पारीक, गोपीकिशन छिंपा, महादेव नाई, बलदेव शर्मा, मनीष पारीक, भीमसेन भाटी, महेंद्र तंवर, सीताराम सारस्वत, देवकिशन, कालू खान, सुंदरलाल, नरेश बिश्नोई, गणेश स्वामी, रामकिशन छिंपा, महेश मीणा, मोडाराम समेत कार्यकर्ता मौजूद रहे।

गोरक्षा संकल्प को राष्ट्रीय पदयात्रा

गायों की रक्षा के लिए बीकानेर से 550 किलोमीटर पैदल चलकर 20 दिन में वृंदावन पहुंचेंगे महावीर

बीकानेर। गायों की रक्षा का संदेश ले बीकानेर से वृंदावन तक की पैदल यात्रा करेंगे बीकानेर के महावीरसिंह राजपुरोहित। राजपुरोहित इस यात्रा में 550 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। इसके लिए उन्हें 20 दिन का समय लगेगा। वे हर रोज करीब 30 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। राजपुरोहित के साथ आर्यन जोशी मोटरसाइकिल पर चलेंगे। वे बीकानेर से रायसर, श्रीडूंगरगढ़, रतनगढ़, फतेहपुर, लक्ष्मणगढ़, सीकर, थानागाजी, डीग, गोवर्धन होते हुए वृंदावन पहुंचेंगे। राजपुरोहित की वृंदावन तक की पैदल यात्रा शुरू हुई। उन्हें लालेश्वर महादेव मंदिर के अधिष्ठाता स्वामी विमर्शानंद महाराज, उप महापौर राजेंद्र पवार, भाजपा के महामंत्री मोहन सुराणा, जनसंपर्क विभाग के उपनिदेशक हरिशंकर आचार्य, साइबर थाने के उपाधीक्षक मानाराम गर्ग ने हरिझंडी दिखाकर रवाना किया।

इस दौरान सीआई गोविंद व्यास, संस्कृतिकर्मी शिवकुमार शर्मा, पार्षद अनूप गहलोत, गोपीनाथ मंदिर ?विकास समिति के सचिव राजकुमार जोशी, महावीर सिंह, बाबूसिंह राजपुरोहित समेत अनेक लोग उपस्थित थे। विदित रहे कि गोरक्षा के लिए राजपुरोहित 10 हजार किलोमीटर की पद यात्रा करेंगे, जिसमें से अब तक 1750 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर चुके हैं। वृंदावन की यात्रा पूरी करने के बाद करीब 2300 किमी की यात्रा पूरी हो जाएगी। अब तक राजपुरोहित ने इन क्षेत्रों तक की पैदल यात्रा महावीरसिंह राजपुरोहित ने गायों की रक्षा के लिए 2019 से अब तक तीन यात्रा पूरी कर ली है। इस बार चौथी वृंदावन तक की पदयात्रा चौथी पदयात्रा होगी। उन्होंने 2019 में बीकानेर से अंबाजी, गुजरात की 500 किमी, 2021 में जालौर से धूमड़ा माताजी 450 किमी की यात्रा की। इसके अलावा 2022 में बीकानेर से उज्जैन महाकाल तक की 750 किमी की है। पदयात्रा का जगह-जगह स्वागत पदयात्री महावीर सिंह राजपुरोहित का जगह-जगह स्वागत किया गया। डूंगर कॉलेज के सामने, उदासर फांटा, हल्दीराम प्याऊ के सामने स्वागत किया। हल्दी राम प्याऊ पर एक स्कूल की ओर से आयोजित कार्यक्रम में पदयात्री राजपुरोहित का महेंद्र सिंह बीदावत, स्कूल संचालक महावीर सिंह राजपुरोहित, श्रवण कुमार सैनी, अंजू प्रजापत, हेमंत कुमार, दुर्गा देवी और प्रवीण भाटी समेत कई लोगों ने स्वागत किया।

अग्र सावन मेला 25 जुलाई से, तीन दिन चलेगा

बीकानेर। अग्रवाल समाज चेतना समिति महिला प्रकोष्ठ की ओर से 25 जुलाई से तीन दिवसीय अग्र सावन मेला लगाया जाएगा। मेले के पोस्टर का विमोचन समिति अध्यक्ष सुशील बंसल ने किया।

महिला प्रकोष्ठ प्रभारी डॉक्टर विजयश्री ने बताया कि यह महिला उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए समाज द्वारा किया गया प्रयास है। इस मेले में महिला उद्यमियों द्वारा लगभग 40 स्टॉल लगाई जाएंगी। स्टॉल प्रभारी सुरभि अग्रवाल ने बताया कि तीन दिन के इस मेले में बेडशीट, साड़ी, ज्वेलरी, अचार आयुर्वेदिक उत्पाद, सूट मटेरियल, लड्डू गोपाल पोशाक, खिलौने हैंडीक्राफ्ट आइटम के साथ-साथ टैरो कार्ड एस्ट्रोलॉजर की भी स्टॉल होगी। गेम प्रभारी स्मिता अग्रवाल ने बताया कि ग्राहकों के मनोरंजन के लिए प्रतिदिन तंबोला गेम तथा अन्य गेम भी रखे गए हैं। इसके साथ-साथ फूड स्टॉल भी लगाई जाएगी।

निशा अग्रवाल और आराधना चौधरी ने बताया कि पैम्फलेट की फोटो कम से कम 24 घंटे पहले फेसबुक इंस्टाग्राम स्टेटस पर लगाने और कम से कम 5 व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करने वाले ग्राहक को तम्बोला का फ्री टिकट भी दिया जाएगा। स्टॉल रजिस्ट्रेशन और व्यवस्था मनीष चौधरी, कीर्ति बंसल, कनुप्रिया गुप्ता, वंदना गोयल के जिम्मे रहेगी।

दहेज नही देने पर गर्भवती महिला से की मारपीट, मामला दर्ज

नदबई। लखनपुर थाना क्षेत्र के गांव नगला डिप्टी निवासी नीरज सैनी ने गर्भवती होने के बावजूद दहेज की मांग करते मारपीट कर प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए अपने पति सहित ससुरालजनों के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज कराया। पुलिस के अनुसार पीडित महिला की करीब चार साल पहले भुसावर निवासी नीरज सैनी के साथ शादी हुई। शादी के बाद ससुरालजन दहेज में दो लाख नगदी की मांग करते हुए महिला को प्रताड़ित करने लगे। इतना ही नही करीब एक पखवाड़े पहले गर्भवती होने के बावजूद विवाहित महिला से मारपीट की गई। जिसके चलते पीडित महिला ने अपने पति नीरज सैनी सहित सास कमला व ससुर यादराम सैनी के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज कराया। उधर, लखनपुर थाना क्षेत्र के गांव गादौली निवासी सपना जाटव ने दहेज में गाडी मांगने व दहेज नही देने पर मारपीट कर प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए विकास नगर भरतपुर निवासी पति पंकज जाटव, ससुर प्रेमसिंह , सास देवकी, जेठ रामवीर, विक्रम व लोकेन्द्र , जिठानी पुष्पलता, रीना व उमेश सहित भतीजे जतिन खिलाफ मामला दर्ज कराया।

बिजली पोल पर काम करते लगा करंट, ऊंचाई से गिरा हेल्पर

फॉल्ट ठीक करने खंभे पर चढ़ा था, हादसे का सीसीटीवी आया सामने

कोटा। बिजली के पोल पर काम करते समय करंट लगने से हेल्पर नीचे गिर गया। करीब 12 फीट ऊंचाई से गिरने से हेल्पर को चोट लगी। घटना कोटा के कैथून के सुमन विहार कॉलोनी में सुबह 9 बजे के आस-पास की है। हेल्पर के पोल से गिरने का सीसीटीवी भी सामने आया है।

हेल्पर भूपेंद्र (26) के बिजली के खंबे से नीचे गिरने पर तुरंत कोटा के निजी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। उसकी हालत गम्भीर बनी हुई है। भूपेंद्र के चाचा अर्जुन ने बताया कि वह रानीपुरा गांव में रहता है। पिछले दो साल से बिजली विभाग में ठेके पर गाड़ी चलाता है। आज सुबह बिजली की कॉल पर फाल्ट ठीक करने गया। उसके साथ 2 लाइन मेन सहित 3-4 अन्य लोग थे। शट डाउन ले रखा बताया। फाल्ट को ठीक करने लाइनमेन बिजली के पोल पर नहीं चढ़े बल्कि भूपेंद्र को बिजली के पोल पर चढ़ा दिया।

सिर का ऑपरेशन हुआ : बिजली के पोल के ऊपर से 11 केवी की लाइन गुजर रही थी। काम करते समय भूपेंद्र 11 केवी लाइन की चपेट में आ गया। करंट का झटका लगते ही पोल से नीचे गिर गया। उसके गिरने की आवाज सुनकर आसपास के लोग मदद के लिए पहुंचे। साथ में मौजूद लोग उसे इलाज के लिए हॉस्पिटल लेकर पहुंचे। भूपेंद्र के सिर में गहरी चोट लगी है। उसके सिर का ऑपरेशन हुआ है।

लाइनमेन बोला- केवल सीढ़ी लगाने को कहा था : जयपुर विद्युत वितरण निगम के AEN जेपी नागर ने बताया- भूपेंद्र ठेके पर हेल्पर के रूप में FRT में काम करता है। आज LT लाइन में फाल्ट की कॉल पर गया था। उसके साथ JVVNL के 2 व एक ठेका फर्म का लाइन मेन था। सुबह 9 से 10 बजे के बीच FRT की टीम काम कर रही थी। LT लाइन ले फाल्ट को ठीक करने की जिम्मेदारी ठेका फर्म की है। ठेका फर्म के लाइन मेन को पोल पर चढ़ना चाहिए था।

ठेका फर्म के लाइनमेन प्रमोद का कहना है कि उसने केवल सीढ़ी लगाने को कहा था। अब भूपेंद्र अपनी मर्जी से चढ़ा या किसी के कहने पर पोल पर चढ़ा ये साफ नहीं हुआ। इस बारें में अधिकारियों को सूचना दी है। जांच के बाद ही स्थिति साफ होगी।

महात्मा गांधी स्कूलों में आवेदन की डेट्स बढ़ी

अब 25 जुलाई की रात बारह बजे तक शाला दर्पण पोर्टल पर हो सकेगा ऑनलाइन आवेदन

बीकानेर। प्रदेश के सरकारी अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में रिक्त पड़े पदों के लिए आवेदन करने वाले टीचर्स को अब 22 जुलाई के बजाय 25 जुलाई की रात बारह बजे तक ऑनलाइन आवेदन की छूट दी गई है।उम्मीद से कम आवेदन आने के कारण लास्ट डेट में बढ़ोतरी की गई है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक आशीष मोदी की ओर से जारी आदेश में महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम स्कूल, स्वामी विवेकानन्द राजकीय आदर्श स्कूल और सभी अंग्रेजी मीडियम स्कूल में रिक्त पदों पर आवेदन मांगे गए हैं। इसकी लास्ट डेट 22 जुलाई तय की गई थी, जिसे अब बढ़ाकर 25 जुलाई कर दिया गया है। जिन टीचर्स ने पहले

आवेदन किया हुआ है, उन्हें अब नए सिरे से आवेदन की जरूरत नहीं है। जिन टीचर्स ने आवेदन सबमिट नहीं किया है, उन्हें अब आवेदन को 25 जुलाई तक सबमिट करने का अवसर मिल गया है। माना जा रहा है कि कई जिलों में आवेदन काफी कम आए हैं, ऐसे में एक बार डेट्स में बढ़ोतरी की गई है। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में सेशन शुरू हो चुका है लेकिन अब तक टीचर्स नहीं पहुंच सके हैं। खासकर बीकानेर के महात्मा गांधी स्कूल में रिक्त पदों के चलते पढ़ाई बाधित हो रही है। बीकानेर के मुरलीधर व्यास नगर और सूरसागर स्थित अंग्रेजी माध्यम स्कूल में स्टूडेंट्स ज्यादा है लेकिन यहां भी कई पद रिक्त पड़े हैं।

रेलयात्रा के मार्ग में परिवर्तन

बीकानेर से कोलकाता जाने वाली रेल प्रयागराज में नए रूट से जाएगी

बीकानेर। बीकानेर से कोलकाता जाने वाली रेल सेवा के मार्ग में फेरबदल किया गया है। दरअसल, प्रयागराज रेलवे स्टेशन पुनर्विकास कार्य के विस्तार के कारण रेल यातायात प्रभावित हो रहा है। जिन रेल गाड़ियों में फेरबदल किया गया है।

रेलवे की ओर से जारी गाइड लाइन में बताया गया है कि गाडी संख्या 12495, बीकानेर-कोलकाता साप्ताहिक रेलसेवा दिनांक 08.08.24 तक बीकानेर से प्रस्थान करेगी वह परिवर्तित मार्ग आगराकैंट-विरांगना लक्ष्मीबाई झांसी-मनिकपुर-प्रगयाराज छिवकी-पं. दीनदयाल उपाध्याय होकर संचालित होगी। उत्तर मध्य रेलवे के प्रयागराज स्टेशन पर लाइन 5 व 7 (प्लेटफार्म नं. 4 व 5) पर एयर कोनकोर्स निर्माण कार्य के विस्तार के कारण ब्लॉक लिया जा रहा है, जिससे रेल यातायात प्रभावित रहेगा। ये मार्ग कब तक बाधित रहेगा, इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। फिलहाल अगले कुछ दिन तक परिवर्तित रेल मार्ग से ही गाड़ी चलेगी।

उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण के अनुसार उपरोक्त कार्य हेतु उत्तर पश्चिम रेलवे पर संचालित निम्न रेलसेवाएं की मार्ग परिवर्तित की तारीख में विस्तार किया जा रहा है। गाडी संख्या 12396, अजमेर-राजेन्द्रनगर साप्ताहिक रेलसेवा नौ अगस्त 24 तक अजमेर से प्रस्थान करेगी, वह परिवर्तित मार्ग आगराकैंट-विरांगना लक्ष्मीबाई झांसी-मनिकपुर-प्रगयाराज छिवकी-पं. दीनदयाल उपाध्याय होकर संचालित होगी। यात्रियों को भी इस बारे में जानकारी दी गई है।

5 मिनट तक बिजली लाइन से चिपका रहा, जिंदा बचा : तड़पता देखकर बचाने चढ़े लोग, फिर क्रेन बुलाई; भाई के तीये की बैठक छोड़कर आया था

रामगंज मंडी (कोटा)। भाई के तीये की बैठक छोड़कर बिजली की लाइन को ठीक करने पहुंचे ठेकाकर्मी के करंट लग गया। 5 मिनट तक लटका रहा। व्यापारियों ने जेईएन को फोन कर सप्लाई को बंद कराया। क्रेन के जरिए उसे नीचे उतारा और अस्पताल ले गए। मामला कोटा के रामगंज मंडी का दोपहर 1 बजे का है।

प्रत्यक्षदर्शी और व्यापारी लोकेश पावेचा ने बताया- कृषि उपज मंडी प्रशासन ने बिजली नियंत्रण के लिए ठेके पर 3 निजी लोगों को लगा रखा है। मंडी परिसर में लाइट नहीं आ रही थी। ऐसे में बुरनखेड़ी निवासी बालचंद धाकड़ (65) दोपहर 1 बजे बिंडी बाजार के पोल पर चढ़ा। उसने जैसे ही बिजली के तारों को छुआ तो करंट लग गया। 5 मिनट तक वह पोल पर लटका रहा। इस दौरान लोगों में अफरा-तफरी मच गई। लोगों ने जेईएन को फोन कर सप्लाई बंद कराई।

क्रेन के जरिए नीचे उतारा

व्यापारी लोकेश ने बताया- बिजली सप्लाई बंद कराने के बाद व्यापारियों ने पोल पर चढ़कर ठेकाकर्मी को उतारने का प्रयास किया, लेकिन

कामयाब नहीं हुए। इसके बाद बिजली विभाग की क्रेन मौके पर पहुंची और उसको उतारा गया। एंबुलेंस नहीं आने पर घायल कर्मी को निजी वाहन से रामगंजमंडी सीएचसी लेकर पहुंचे, जहां उसका उपचार किया जा रहा है।

डॉ.गोविंद यादव ने कहा कि समय रहते ठेकाकर्मी को हॉस्पिटल लेकर पहुंच गए थे। इसलिए हालत स्थिर है। हालांकि करंट शरीर के आंतरिक हिस्सों को नुकसान पहुंचाता है। ऐसे में उनको हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है।

ठेकेदार को पाबंद किया जाएगा : ग्रेन एंड सीट्स मर्चेंट एसोसिएशन अध्यक्ष मुकेश धाकड़ ने बताया कि कृषि उपज मंडी में लाइटिंग व्यवस्था के किए ठेका दिया हुआ है, जिसमें 3 कर्मी लगे हुए हैं। जो रोड लाइट का काम देखते हैं। ऐसी घटना दोबारा न हो इसके लिए ठेकेदार को सुरक्षा उपकरण और बिजली विभाग की गाइडलाइन की पालना के लिए पाबंद किया जाएगा।

मंडी में लगे हैं निजी कर्मी : बिजली विभाग सहायक अभियंता सीएम जारवाल ने बताया- कृषि उपज मंडी में लाइटिंग व्यवस्था को लेकर करीब 15 पोल लगे हुए हैं। जिसमें एलटी लाइन से दुकानों में सप्लाई दी हुई है। कृषि उपज मंडी से मेंटेनेंस को लेकर निजी कर्मी लगाए हुए हैं। कर्मी ने बिजली विभाग से लाइन बंद नहीं करवाई और पोल पर चढ़ गया। ऐसे में लाइन चालू थी और करंट की चपेट में आ गया। मामले में बिजली विभाग संबंधित अधिकारियों को नोटिस देगा और इसकी रिपोर्ट उच्चाधिकारियों को भेजी जाएगी।

भाई के तीये की बैठक थी : बालचंद के बेटे दिनेश ने बताया कि पिताजी 12 साल से कृषि उपज मंडी में लाइटिंग का काम संभाल रहे हैं। 20 जुलाई को चाचा भाई दुर्गा लाल की हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। तीये की बैठक थी। कृषि उपज मंडी की लाइन बंद होने की सूचना पर पिताजी बैठक छोड़कर इमरजेंसी में लाइट दुरुस्त करने पहुंचे थे।

नदबई में दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज

चार पहिया गाड़ी मांगने का आरोप, पुलिस ने दर्ज किया मामला

नदबई। नदबई में दहेज में चार पहिया गाड़ी की डिमांड को लेकर ससुराल वालों ने विवाहिता से मारपीट कर घर से निकालने का मामला सामने आया है। पीड़िता ने पति सहित ससुराल वालों के खिलाफ लखनपुर थाने में मामला दर्ज कराया है। पुलिस के अनुसार गादौली थाना लखनपुर निवासी सपना पुत्री मानसिंह जाटव ने मामला दर्ज कराया है कि पीड़िता सपना की शादी विकास नगर आरबीएम हॉस्पीटल के पीछे भरतपुर निवासी पंकज पुत्र प्रेमसिह के साथ 30 जनवरी 2015 को संपन्न हुई थी। पीड़िता के पिता ने शादी में सामर्थ्य के अनुसार दान दहेज दिया था। मगर पीड़िता का पति पंकज, ससुर प्रेमसिंह, सास देवकी, जेठ सहित अन्य ससुरालजन पीड़िता को कम दहेज लाने के लिए ताने देने लगे और दहेज में चार पहिए की गाड़ी लाने की मांग करने लगे। पीड़िता ने दर्ज मामले में बताया है की शादी के बाद से ही ससुराल वाले उसे भूखी प्यासी रख मारपीट करते चले आ रहे है।

पीड़िता ने बताया कि वह अब अपने माता-पिता के साथ गांव गादौली में रह रही है। पीड़िता के घर वालों ने ससुराल वालों को कई बार समझाने का प्रयास किया, लेकिन वह नहीं माने और दहेज की मांग पर अड़े रहे। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

मथुरा में पीएसी के जवान ने खुद को गोली मारी, मौत

मथुरा। श्रीकृष्ण जन्मभूमि की सुरक्षा में तैनात एक पीएसी के जवान ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। प्राथमिक जांच में आत्महत्या के कारणों पता नहीं चला है। 15वीं बटालियन के एक जवान ने अपनी बैरक में कथित रूप से गोली मारकर आत्महत्या कर ली। जवान ने सरकारी सर्विस राइफल से खुद को गोली मारी थी। 23 जुलाई को ही उसका जन्मदिन भी था। पुलिस ने पोस्टमार्टम के पश्चात शव उसके परिजनों को सौंप दिया है। पुलिस अधीक्षक (नगर) अरविंद कुमार ने बताया कि सोमवार रात पीएसी के प्लाटून कमाण्डर ने सूचना दी थी कि श्रीकृष्ण जन्मस्थान की सुरक्षा ड्यूटी कर रहे जवान सुधीर मलिक (25) ने हाईवे थानाक्षेत्र में स्थित पीएसी बैरक में सरकारी राइफल से गोली मारकर आत्महत्या कर ली। सुधीर गौतमबुद्ध नगर के निवासी थे।

ममता बनर्जी के कार्यक्रम में बड़ा हादसा, ऑडिटोरियम का गिरा गेट, कई घायला

कोलकाता। कोलकाता में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के कार्यक्रम में एक अस्थायी गेट गिर गया। घटना के बाद लोगों के घायल होने की खबर है लेकिन अभी तक घायलों की संख्या नहीं बताई गई है। यह कार्यक्रम सूचना एवं सांस्कृतिक कार्य विभाग द्वारा महान अभिनेता उत्तम कुमार की 44वीं पुण्य तिथि के अवसर पर धनधान्य सभागार में आयोजित किया गया था। घटना के वीडियो में एक शख्स घायल नजर आ रहा है और कुछ लोग उसे एंबुलेंस की ओर ले जा रहे हैं। 13 अप्रैल, 2023 को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा सभागार का अनावरण किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री फिल्मी हस्तियों को महानायक पुरस्कार प्रदान करने वाले थे। 2021 में सत्ता बरकरार रखने के बाद, तृणमूल कांग्रेस के नेतृत्व वाली राज्य सरकार राज्य के अब तक के सबसे लोकप्रिय अभिनेता की पुण्यतिथि मनाती है। 24 जुलाई 1980 को जन्मे उत्तम कुमार को उनकी लोकप्रिय फिल्मों के लिए जाना जाता है, जिनमें 1956 साहेब बीबी गोलाम, 1957 हरानो सूर और 1961 सप्तपदी शामिल हैं।

महाराष्ट्र और गुजरात में बाढ़ से बिगड़े हालात

गढ़चिरौली। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में पिछले कई दिनों से भारी बारिश के कारण नदी और नाले उफान पर हैं। बाढ़ के कारण करीब 15 गांव पानी में डूब चुके हैं। गढ़चिरौली में भारी बारिश की वजह से हालात लगातार खराब हो रहे हैं। बाढ़ का पानी कई गांवों के अंदर तक घुस गया है। इससे ग्रामीणों को खाने-पीने के लिए परेशानी उठानी पड़ रही है। वहीं, प्रशासन की ओर से बाढ़ से निपटने के लिए खास इंतजाम किए हैं। बाढ़ के हालातों के चलते एहतियात के तौर पर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों मार्गों को बंद कर दिया गया है। जिससे लोगों को आने-जाने में परेशानी हो रही है। वहीं गुजरात के कच्छ में भी बाढ़ का कहर जारी है। भारी बारिश के कारण संघाना नदी में बाढ़ आ गई। इससे बेहद दर्दनाक हादसा हुआ। बाढ़ की चपेट में आने से करीब 15 गायें नदी में बह गईं। गुजरात सरकार ने बाढ़ की स्थिति को देखकर प्रभावितों तक हर संभव मदद पहुंचाने का निर्देश दिया है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्रभाई पटेल ने बाढ़ प्रभावित कई जिलों का हवाई निरीक्षण किया। सीएम पटेल ने बताया कि सौराष्ट्र के तटीय जिलों में भारी बारिश के कारण पैदा हुए हालातों का जायजा लिया। जामनगर और द्वारका जिलों के गांवों का हवाई निरीक्षण करने के बाद दोनों जिलों के अधिकारियों व पदाधिकारियों के साथ बैठक कर राहत एवं बचाव उपायों की समीक्षा की। उन्होंने कहा, भारी बारिश के दौरान लोगों की सुरक्षा के लिए जिला प्रशासन को तेजी के साथ काम करने का निर्देश दिया है।

हिमाचल प्रदेश : मौसम विभाग ने 28 जुलाई तक भारी बारिश का 'येलो' अलर्ट जारी किया

शिमला। हिमाचल प्रदेश में मौसम विभाग ने बुधवार को राज्य के अलग-अलग स्थानों पर अगले चार दिन यानी 28 जुलाई तक भारी बारिश का 'येलो' अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग ने राज्य में तेज हवाओं और निचले इलाकों में जलभराव के कारण बागानों एवं खड़ी फसलों और कच्चे घरों को नुकसान होने के बारे में चेतावनी भी दी। शिमला स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार, राज्य के कुछ हिस्सों में रुक-रुक कर बारिश हो रही है। केंद्र के मुताबिक, मंगलवार शाम से बैजनाथ में 85 मिलीमीटर (मिमी) बारिश दर्ज की गई जबकि पालमपुर में 25.2 मिमी, जोगिंदरनगर में 18 मिमी, धर्मशाला में 10.4 मिमी, सैंज एवं काहू में 7.5-7.5 मिमी, कसौली में 7.4 मिमी और शिमला में 5.6 मिमी बारिश दर्ज की गई। आपात केंद्र ने बताया कि राज्य में अब तक बारिश से संबंधित घटनाओं में 47 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि 27 जून से जारी मानसून में लगभग 364 करोड़ रुपये का नुकसान हो चुका है।

भरतपुर में गौ तस्करों के बीच गैंगवार,एक की गोली लगने से मौत

भरतपुर। कुम्हेर थाना अंतर्गत जंगीपुर पिचूमर गांव के पास एक गो तस्कर की गोली लगने से मौत हो गई है। घटना की सूचना मिलते ही कुम्हेर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर कुम्हेर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की मोर्चरी में रखवाया। जानकारी के मुताबिक यह घटना रात्रि करीब 2:00 बजे कुम्हेर थाना इलाके में जंगीपुर पिचूमर गांव के पास की बताई जा रही है। घटना के संबंध में पुलिस अधिकारी मीडिया को अभी कुछ जानकारी नहीं दे रहे हैं। घटना की जांच की जा रही है और पुलिस सभी पहलुओं की गहनता से जांच कर रही है। घटना से स्थानीय निवासियों में भय और तनाव का माहौल है। गो तस्करी की समस्या और इससे जुड़े अपराधों को लेकर लोग चिंतित हैं। कुछ स्थानीय निवासियों ने गो तस्करी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। यह घटना गो तस्करी के जटिल और खतरनाक नेटवर्क को उजागर करती है, जहां आपसी विवाद में हिंसा की घटनाएं आम हो रही हैं। पुलिस द्वारा इस मामले की जांच के बाद ही पूरी जानकारी सामने आ पाएगी। उम्मीद की जा रही है कि पुलिस जल्द से जल्द इस मामले को सुलझाएगी और दोषियों को पकड़कर न्याय दिलाएगी। मृतक गो तस्कर की पहचान डीग के पास सौनगाव निवासी के रूप में हुई है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, गो तस्करों के आपसी विवाद में एक गो तस्कर ने दूसरे गो तस्कर को गोली मार दी, जिससे उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही कुम्हेर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। आईजी राहुल प्रकाश और पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार सहित अन्य उच्च अधिकारी भी घटना स्थल पर पहुंचे और मामले की जांच की। पुलिस ने मृतक गो तस्कर के शव को कब्जे में लेकर कुम्हेर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की मोर्चरी में रखवाया है।

रातभर चले एनकाउंटर में एक आतंकी ढेर, सेना का जवान घायल

जम्मू। बीती रात जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के जमकर फायरिंग हुई। इसमें एक आतंकी ढेर हो गया और सेना का एक जवान घायल हुआ है। सेना ने कहा कि मंगलवार को संदिग्ध गतिविधियां दिखाई देने पर सैनिकों ने संदिग्धों को चुनौती दी। इस पर आतंकवादियों ने अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी और दोनों ओर से मुठभेड़ शुरू हो गई। सेना ने कहा कि मुठभेड़ में एक आतंकवादी मारा गया और एक सैनिक घायल हो गया। अभियान जारी है। श्रीनगर की चिनार कोर ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर अपने पोस्ट में कहा, कुपवाड़ा के कोवुत इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में खुफिया जानकारी मिलने पर भारतीय सेना और जम्मू-कश्मीर पुलिस ने 23-24 जुलाई को संयुक्त तलाश अभियान शुरू किया। सूत्रों के अनुसार, सैनिकों को कृष्णाघाटी के बट्टल अग्रिम क्षेत्र में आतंकवादियों के समूह की गतिविधियों का पता चला और उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। सूत्रों ने बताया कि लांस नायक सुभाष कुमार भीषण मुठभेड़ में घायल हो गए और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। उन्होंने बताया कि आतंकवादियों को भी नुकसान पहुंचा है। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि सैनिक का पार्थिव शरीर पोस्टमॉर्टम के बाद सेना को सौंप दिया गया है। हाल के महीनों में जम्मू में आतंकी गतिविधियां बढ़ी हैं, जिससे क्षेत्र में आतंकवाद के फिर से सिर उठाने की आशंका बढ़ गई है। बता दें कि इसके पहले, जम्मू-कश्मीर के पुंछ जिले में मंगलवार तड़के नियंत्रण रेखा (एलओसी) के पास आतंकवादियों की घुसपैठ की कोशिश को सेना ने नाकाम कर दिया, जिस दौरान एक जवान शहीद हो गया था।व्हाइट नाइट कोर ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, सतर्क सैनिकों ने तड़के तीन बजे बट्टल सेक्टर में घुसपैठ कर रहे आतंकवादियों की गोलीबारी का माकूल जवाब देकर घुसपैठ की कोशिश नाकाम कर दी। कोर ने कहा, भारी गोलीबारी के दौरान एक वीर जवान घायल हो गया। अभियान जारी है।

कुर्सी बचाने वाला बजट बताने पर विपक्ष पर भड़की वित्त मंत्री सीतारमण

-राज्यसभा में कांग्रेस को दे डाली चुनौती कहा-आप अपने हर बजट का भाषण दिखाएं

नई दिल्ली (एजेंसी)। मंगलवार को देश सदन में देश का आम बजट वित्त मंत्री सीतारमण ने पेश किया था। इस बजट को लेकर बुधवार को संसद में जोरदार हंगामा हो गया है। राज्यसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे ने बजट को भेदभावपूर्ण बताया और कहा कि यह बजट कुर्सी बचाने वाला है। खड़गे ने आरोप लगाते हुए कहा कि इस बजट में ना तमिलनाडु, न कर्नाटक, न हरियाणा, न राजस्थान, और ना ओडिशा को कुछ मिला है। किसी को खुश करने के लिए यह बजट है। खड़गे के इस आरोप पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भड़क गईं और बजट में राज्यों के नाम पर कांग्रेस को चुनौती दे डाली और सवाल किया कि क्या आपने अपने सभी बजट भाषणों में सभी राज्यों का नाम लिया था?

विपक्ष का आरोप है कि इस बजट में केवल दो राज्यों बिहार और आंध्र प्रदेश को ही फंड दिया गया बाकी राज्यों को कुछ खास नहीं मिला दिया। उधर सीतारमण ने इस आरोप को 'अपमानजनक' करार देते हुए कहा कि कांग्रेस लोगों के मन में यह धारणा बनाने की कोशिश कर रही है कि दूसरे राज्यों को कुछ नहीं दिया गया है। सीतारमण ने विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि आप अपना हर बजट भाषण हमें दिखाइए कि आपने अपने समय में हर राज्य का नाम लिया था। हमने अपने बजट भाषण में सभी राज्यों का नाम नहीं लिया, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हमने उन राज्यों को कुछ नहीं दिया है।

उन्होंने कहा कि कैबिनेट ने वधावन में एक बंदरगाह स्थापित करने का निर्णय लिया था, लेकिन बजट में महाराष्ट्र का नाम नहीं लिया गया तो इसका मतलब यह है कि महाराष्ट्र को कुछ नहीं दिया है? अगर भाषण में किसी विशेष राज्य का नाम लिया जाता है, तो क्या इसका मतलब यह है कि सरकार के कार्यक्रम इन राज्यों में नहीं जाते हैं? यह कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्ष का लोगों को यह धारणा बनाने का एक जानबूझकर प्रयास है कि अन्य राज्यों को कुछ नहीं दिया है। यह एक अपमानजनक आरोप है।

वित्त मंत्री ने कहा कि महाराष्ट्र को हमने 6000 करोड़ रुपए दिए, लेकिन भाषण में इसका जिक्र नहीं किया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बंगाल को 10 साल में कई योजनाएं दी गईं, लेकिन बंगाल ने केंद्र की योजनाओं को लागू नहीं किया और अब वे सवाल कर रहे हैं। सीतारमण के इस आरोप पर बंगाल की सांसद भड़क गईं और फिर सदन में हंगामा शुरू हो गया। इससे पहले खड़गे ने विपक्ष की तरफ से मोर्चा संभालते हुए सरकार पर आरोप लगाया, 'कुर्सी बचाने के लिए यह सब हुआ हैज हम इसकी निंदा करेंगे और इसका विरोध करेंगे। इंडिया गठबंधन के सभी दल इसका विरोध करेंगेज्अगर संतुलन नहीं होगा तो विकास कैसे होगा?' इसके साथ ही विपक्षी दल के सभी सदस्य राज्यसभा से वॉकआउट कर गए।

सालों बाद संसद परिसर में हंसी-ठिठौली करती दिखीं सोनिया गांधी और जया बच्चन

नई दिल्ली। एक समय था जब गांधी और बच्चन परिवार में गजब का दोस्ताना था। बाद में वक्त बदला ये रिश्ता कमजोर पड़ गया। लेकिन संसद में बुधवार को बदला-बदला नजारा दिखा। कई सालों बाद कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और जया बच्चन के बीच संसद परिसर में हंसी-ठिठौली का माहौल दिखाई दिया। दरअसल, विपक्षी दल केंद्र के बजट का विरोध करने एकत्र हुए थे। तभी सोनिया और जया बच्चन बातचीत करती नजर आईं। जिस तरह सोनिया और जया के बीच संसद भवन परिसर में बातचीत होती दिखी। हाल के वर्षों में ये पहला मौका है जब सोनिया और जया के बीच इतने गर्मजोशी वाले माहौल में बातचीत होती दिखी। एक वक्त सोनिया के पति और पूर्व पीएम राजीव गांधी और अमिताभ बच्चन के बीच दोस्ती की मिसाल दी जाती थी। दरअसल, संसद की कार्यवाही में भाग लेने जैसे ही सोनिया गांधी पहुंची वहां कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला ने उनका स्वागत किया। तभी जया बच्चन को देखकर सोनिया गांधी मुस्कुराईं और बातचीत करने लगीं। इसके बाद किसी बात पर सोनिया और जया हंसने लगीं। सोनिया ने कुछ ऐसी बात कही जिसपर जया ठहाके मारकर हंसने लगीं। ये पूरा मामला तब सामने जब केंद्रीय बजट पेश होने के अगले ही दिन विपक्ष ने इसके विरोध में आवाज बुलंद की। विपक्ष ने बजट में कुछ राज्यों पर ही फोकस करने के आरोप लगाए।

ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड लैमी दो दिवसीय यात्रा पर भारत आए

-एफटीए और खालिस्तान समर्थकों की गतिविधियों को लेकर हो सकती है चर्चा

नई दिल्ली (एजेंसी)। ब्रिटिश विदेश मंत्री डेविड लैमी बुधवार को दो दिवसीय यात्रा पर भारत आए। लैमी और भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के बीच भारत-ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) और ब्रिटेन में खालिस्तान समर्थकों की गतिविधियों पर भारत की चिंताओं पर चर्चा होने की उम्मीद है। दोनों के बीच रूस और यूक्रेन जंग और मध्य पूर्व की स्थिति समेत गंभीर वैश्विक चुनौतियों पर भी विचार-विमर्श होने की उम्मीद है।

विदेश मंत्रालय ने अपनी पोस्ट में कहा कि पदभार ग्रहण करने के बाद ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड लैमी का नई दिल्ली पहुंचने पर हार्दिक स्वागत। उनकी इस यात्रा से दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी मजबूत होगी। इसके साथ ही भारत और ब्रिटेन के बीच संबंध और मजबूत होंगे। बता दें कि ब्रिटेन में नए पीएम कीर स्टार्मर की लेबर सरकार के सत्ता में आने के बाद दोनों पक्षों के बीच यह पहली उच्च स्तरीय बातचीत होगी।

ब्रिटिश विदेश मंत्री भारत के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल से भी मुलाकात कर सकते हैं, दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करने की संभावना है। जानकारी के मुताबिक दोनों पक्ष पहले ही करीब 90 फीसदी व्यापार समझौते पर सहमत हो चुके हैं, लेकिन बचे हुआ 10 फीसदी में ऑटोमोबाइल और स्कॉच व्हिस्की पर आयात शुल्क और व्यापारिक लोगों के लिए वीजा जैसे कई पेचीदा मुद्दे शामिल हैं। हालांकि, दोनों पक्ष जल्द बातचीत खत्म करने के लिए तैयार हैं। बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी और ब्रिटिश पीएम स्टार्मर के बीच छह जुलाई को फोन पर बातचीत हुई थी। इस दौरान दोनों ने ही एफटीए का मुद्दा उठा था। भारत सरकार के एक रीडआउट में कहा गया है कि दोनों नेता पारस्परिक रूप से लाभकारी भारत-ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते को जल्द पूरा करने की दिशा में काम करने पर सहमत हो गए हैं।

पीएम मोदी से फोन पर बातचीत के बाद ब्रिटेन पीएम स्टार्मर ने कहा कि वह एक ऐसे समझौते को खत्म करने के लिए तैयार हैं जो दोनों पक्षों के लिए काम करेगा। विदेश मंत्री जयशंकर और ब्रिटिश विदेश मंत्री लैमी के बीच बातचीत में भारत-ब्रिटेन रोडमैप के कार्यान्वयन की समीक्षा करने की उम्मीद है, जो कई क्षेत्रों में संबंधों को व्यापक आधार देना चाहते हैं। 2021 में, भारत और यूके ने व्यापार और अर्थव्यवस्था, रक्षा और सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन और लोगों से लोगों के बीच कनेक्शन जैसे प्रमुख क्षेत्रों में संबंधों का विस्तार करने के लिए 10 साल का रोडमैप बनाया।

विधानसभा में मुझ पर हुआ हमला, शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी विधायक पर लगाए आरोप, कहा- दोबारा ऐसा हुआ तो...

नई दिल्ली (एजेंसी)। भाजपा विधायकों ने आज राज्य में महिला सुरक्षा के मुद्दे पर पश्चिम बंगाल विधानसभा के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। पश्चिम बंगाल विधानसभा के एलओपी और बीजेपी नेता सुवेंदु अधिकारी का कहना है, 'पश्चिम बंगाल में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। बीजेपी की महिला विधायकों ने आज विधानसभा में यह सवाल उठाया और उन्होंने आज इस मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन किया। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि टीएमसी विधायक तपन चटर्जी मुझ पर शारीरिक हमला करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले उन्होंने सदन के अंदर भी ऐसा करने की कोशिश की थी। आज उन्होंने मीडिया के सामने मुझे धक्का देने की कोशिश की। अगर दोबारा ऐसा हुआ तो यह स्पीकर की जिम्मेदारी होगी। नंदीग्राम के भाजपा विधायक ने पत्र में इस घटना के लिए किसी तरह बंद्योपाध्याय को जिम्मेदार ठहराया क्योंकि स्पीकर ने विधायकों के निजी अंगरक्षकों को विधानसभा के अंदर प्रवेश की अनुमति नहीं दी थी। अधिकारी ने कहा कि आज दोपहर लगभग 12.20 बजे निचली लॉबी में पूर्बस्थली के विधायक तपन चटर्जी मेरी ओर बढ़े और मुझ पर शारीरिक हमला करने की कोशिश की और अन्य विधायकों और पत्रकारों के सामने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। अधिकारी ने बंद्योपाध्याय को लिखे पत्र में कहा, 'मुझे विधानसभा परिसर के अंदर असुरक्षित महसूस हुआ। अधिकारी ने दावा किया कि विपक्षी विधायक विधानसभा परिसर में सुरक्षित नहीं हैं। सदन के संरक्षक के रूप में, यदि विधानसभा परिसर के अंदर कोई अप्रिय घटना होती है तो आप जिम्मेदार होंगे। मैं आपसे विधायक के खिलाफ उचित कार्रवाई करने का अनुरोध करता हूं। स्पीकर ने बाद में कहा कि उन्होंने अधिकारी के आरोपों की जांच शुरू कर दी है।

संसद में किसान नेताओं से राहुल गांधी ने की मुलाकात, बोले- हम एमएसपी की गारंटी के लिए सरकार पर डालेंगे दबाव

मुंबई (एजेंसी) कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बुधवार को संसद भवन में किसान नेताओं से मुलाकात की। 12 सदस्यीय किसान नेताओं का प्रतिनिधिमंडल संसद भवन में गांधी के कार्यालय पहुंचा था। कथित तौर पर किसान नेताओं ने अपनी लंबे समय से चली आ रही मांगों को पूरा करने के लिए एक निजी विधेयक पेश करने का भी अनुरोध किया। इससे पहले संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजनीतिक) और किसान मजदूर मोर्चा के नेताओं ने देश भर में मोदी सरकार के पुतले जलाने और न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) गारंटी को वैध बनाने के लिए एक नया विरोध प्रदर्शन शुरू करने की अपनी योजना की घोषणा की थी। इस विरोध प्रदर्शन में विपक्ष के निजी विधेयकों के समर्थन में एक 'लंबा मार्च' शामिल होगा। किसान नेताओं से मुलाकात के बाद राहुल गांधी ने कहा कि हमने अपने घोषणापत्र में कानूनी गारंटी के साथ एमएसपी का जिक्र किया है। हमने आकलन कर लिया है और इसे लागू किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि अभी हमारी एक बैठक हुई जिसमें निर्णय लिया गया कि हम I.N.D.I.A गठबंधन के दूसरे नेता से बात करेंगे और सरकार पर दबाव बनाएंगे कि देश के किसानों को एमएसपी की कानूनी गारंटी दी जाए।

शरद पवार के साथ जाने का मन बना चुके हैं क्या अजित पवार? अमित शाह के सामने रख दी ये कैसी डिमांड?

मुंबई (एजेंसी)। विधानसभा चुनाव से पहले सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन के घटक दलों के बीच सीट बंटवारे को लेकर बातचीत तेज होने के बीच महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के दौरान राकांपा के लिए 80-90 सीटों की मांग की है। अमित शाह के साथ अपनी बैठक के दौरान अजीत पवार ने सीट वितरण को जल्द से जल्द अंतिम रूप देने और लोकसभा चुनाव की तरह आखिरी मिनट तक इधर-उधर भटकने से बचने पर जोर दिया। सूत्रों ने कहा कि अजित पवार उन 54 सीटों पर चुनाव लड़ने पर अड़े थे जो संयुक्त राकांपा ने 2019 के विधानसभा चुनावों में जीती थीं। इनके अलावा अजित पवार की नजर पश्चिमी महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और उत्तरी महाराष्ट्र (खानदेश) क्षेत्र से कांग्रेस के खिलाफ 20 सीटों पर लड़ने पर है।

उपमुख्यमंत्री मुंबई में कांग्रेस के खिलाफ अल्पसंख्यक समुदाय के प्रभुत्व वाली 4-5 सीटों पर चुनाव लड़ने के भी इच्छुक हैं। सूत्रों ने कहा कि अजित पवार को अपनी पार्टी से तीन निर्दलीय और तीन कांग्रेस विधायकों के

चुनाव लड़ने का भी भरोसा है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और उपमुख्यमंत्री देवेन्द्र फड़णवीस भी पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के साथ बैठक के लिए सुबह-सुबह दिल्ली पहुंचे। अजित पवार की अमित शाह से मुलाकात आरएसएस से जुड़े एक साप्ताहिक अखबार द्वारा महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में पार्टी की हार के लिए भाजपा के साथ राकांपा के गठबंधन को जिम्मेदार ठहराए जाने के कुछ दिनों बाद हुई है।

अजित पवार के लिए मामला और जटिल हो गया, पिंपरी-चिंचवड़ इकाई के शहर अध्यक्ष सहित पुणे के 28 एनसीपी नेताओं ने पार्टी छोड़कर एनसीपी (शरद पवार) में शामिल हो गए। भाजपा ने लोकसभा चुनाव में लड़ी गई 28 सीटों में से केवल 9 पर जीत हासिल की, जो 2019 में जीती गई 23 सीटों से कम है। अजीत पवार के नेतृत्व वाली राकांपा ने सिर्फ एक सीट, रायगढ़ जीती, जबकि शरद पवार गुट को आठ सीटें मिलीं। इस बीच, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का शिवसेना गुट 100 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए प्रतिबद्ध है, जबकि भाजपा ने 160 से 170 सीटों का लक्ष्य रखा है।

जम्मू-कश्मीर में इस साल नहीं होंगे विधानसभा चुनाव! सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद भी क्यों है भ्रम की स्थिति?

श्रीनगर (एजेंसी)। जम्मू-कश्मीर में आतंकवादी हमलों में बढ़ोतरी ने क्षेत्र में आगामी विधानसभा चुनाव के साथ-साथ अमरनाथ यात्रा पर भी असर डाला है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को इस साल सितंबर से पहले क्षेत्र में विधानसभा चुनाव कराने का निर्देश दिया है। अमरनाथ यात्रा 19 अगस्त को समाप्त हो रहा है। इसी के बाद विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा की उम्मीद की जा रही है। हालांकि, विधानसभा चुनाव को लेकर भी कई सवाल सामने आ रहे हैं। कुछ लोगों का मानना है कि इस साल विधानसभा चुनाव की संभावनाएं बेहद कम है। हालांकि, चुनाव आयोग इस दिशा में आगे बढ़ता दिखाई जरूर दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है कि जल्द ही राज्य में चुनाव होने वाले हैं।

हालांकि, ऐसी अटकलें हैं कि सितंबर तक केवल पंचायत और नगर निगम चुनाव हो सकते हैं, जबकि विधानसभा चुनाव 2025 तक टाले जा सकते हैं। 19 अगस्त को अमरनाथ यात्रा समाप्त होने के बाद स्थानीय निकाय चुनावों की घोषणा होने की उम्मीद है। विधानसभा चुनाव पर सरकार के संकेत भ्रमित करने वाले हैं। प्रधानमंत्री ने 21 जून की अपनी कश्मीर यात्रा के दौरान उल्लेख किया था कि केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव की तैयारी चल रही है। इसके बाद, गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की एक बैठक हुई, जिसमें पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और जम्मू-कश्मीर के पार्टी नेताओं ने भाग लिया। उन्हें स्पष्ट रूप से चुनाव के लिए 'तैयार' रहने का निर्देश दिया गया था।

जून में, भारत के चुनाव आयोग ने जम्मू-कश्मीर में पंजीकृत और अपंजीकृत पार्टियों से 'सामान्य प्रतीक' के आवंटन के लिए आवेदन भी मांगे। 5 जुलाई को जम्मू-कश्मीर चुनावों की निगरानी के लिए भाजपा प्रभारी, केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने चुनाव तैयारियों की निगरानी के लिए एक पार्टी बैठक की। इसके बावजूद, नई दिल्ली के संकेतों के प्रति हमेशा संवेदनशील रहने वाले कश्मीर मीडिया ने बताया है कि महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड में चुनाव व्यवस्था के संबंध में इस महीने की शुरुआत में राजधानी में हुई बैठकों में जम्मू-कश्मीर का बिल्कुल भी उल्लेख नहीं किया गया था। न ही संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री के जवाब में इसका उल्लेख किया गया था।

क्षेत्र में आतंकवादी हमलों के फिर से बढ़ने से संदेह संभवतः और भी बढ़ गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों में हालिया वृद्धि को विधानसभा चुनाव स्थगित करने का कारण नहीं बनाया जाना चाहिए, यह याद दिलाते हुए कि 1996 में भी चुनाव आयोजित किए गए थे जब क्षेत्र में आतंकवाद अपने चरम पर था। उन्होंने कहा कि कुछ लोग

कह रहे हैं कि स्थिति खराब हो गई है और इसलिए चुनाव नहीं होना चाहिए। आपको क्या हुआ? क्या हम इतने कमजोर हैं या हालात इतने ख़राब हो गए हैं कि चुनाव होने के आसार नहीं हैं? हमने 1996 में चुनाव कराए थे और आपको यह मानना होगा कि उस समय और आज की स्थिति में जमीन-आसमान का अंतर है।

हॉस्पिटल सीज पर विवाद,मरीजों का इलाज नहीं करने की धमकी

मैनेजमेंट का आरोप- विधायक मीणा के रिश्तेदार अवैध वसूली करते हैं

द पुलिस पोस्ट

उदयपुर। विधानसभा में उदयपुर के जीबीएच हॉस्पिटल में अवैध निर्माण का मुद्दा उठा। इसके बाद बुधवार को उदयपुर विकास प्राधिकरण (यूडीए) की टीम सीज की कार्रवाई करने पहुंची तो स्टाफ और मेडिकल स्टूडेंट ने विरोध शुरू कर दिया। विरोध के बीच ही टीम हॉस्पिटल के अंदर गई तो स्टाफ ने मरीजों को छोड़कर बाहर आने की चेतावनी दे डाली। सीज की कार्रवाई से नाराज हॉस्पिटल प्रशासन ने उदयपुर ग्रामीण से विधायक फूल सिंह मीणा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। हॉस्पिटल प्रशासन का आरोप है- विधायक मीणा के रिश्तेदार यहां वसूली करते हैं। उनको कोरोना काल के समय से परेशान किया जा रहा है। उदयपुर विकास प्राधिकरण के तहसीलदार डॉ. अभिनव शर्मा, डिप्टी छगन पुरोहित सहित प्रताप नगर, गोवर्धन विलास और भूपालपुरा थाना अधिकारी पुलिस बल के साथ मौजूद हैं। यहां कई बार पुलिस और लोग आमने-सामने हो चुके हैं। मौके पर मौजूद लोग टीम को जनरल अस्पताल के अंदर नहीं जाने देने पर अड़े हैं।

अस्पताल के स्टाफ ने मरीजों को छोड़ने की चेतावनी

यूडीए की टीम सुबह 9.30 बजे जनरल हॉस्पिटल के अंदर का कुछ भाग सीज करने करने पहुंची तो हॉस्पिटल स्टाफ और स्टूडेंट ने अंदर नहीं जाने दिया। स्टाफ ने चेतावनी दी कि वे सभी मरीजों को छोड़कर आ जाएंगे। इसकी सारी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। बताया जा रहा है कि अभी अस्पताल में करीब 650 मरीज भर्ती हैं। इसके अलावा यहां 2500 का स्टाफ है। हॉस्पिटल स्टाफ ने प्रशासन को चेताया कि वे आईसीयू से लेकर सभी वार्ड में भर्ती मरीजों को छोड़कर बाहर आ जाएंगे और इलाज नहीं करेंगे। मरीजों के इलाज की बात आने के बाद यूडीए की टीम जनरल अस्पताल में सीज की कार्रवाई नहीं कर पाई। टीम में शामिल तहसीलदार डॉ. अभिनव शर्मा ने यूडीए कमिश्नर राहुल जैन से फोन पर बात कर पूरी स्थिति से अवगत कराया।

उदयपुर ग्रामीण विधायक के खिलाफ नारेबाजी

उधर, टीम ने विरोध के बीच कैंपस के पीजी हॉस्टल में चौथी मंजिल से 8वीं मंजिल तक के भाग को सीज कर दिया। रेजिडेंट परिसर में भी 2 बिल्डिंग की ऊपर की मंजिल को सीज किया है। सीज की कार्रवाई होने पर हॉस्पिटल स्टाफ और स्टूडेंट ने उदयपुर ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी।

अस्पताल मैनेजमेंट का आरोप- बेवजह परेशान किया जा रहा है

जीबीएस के पीआरओ भवभूति भट्ट ने बताया कि विधायक फूल सिंह मीणा कोविड के समय से हमारे अस्पताल के खिलाफ किसी न प्रकार का मुद्दा उठा कर बेवजह परेशान कर रहे है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि उनका एक रिश्तेदार हिम्मत मीणा यहां पर आकर वसूलियों का काम करता है। चुनाव के समय से वह सक्रिय है। इस तरह का वह षड्यंत्र कर बेवजह अस्पताल प्रबंधन को परेशान करवा रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले 50 साल की बात करें तो राजस्थान में किसी अस्पताल को पहली बार इस तरह की पहली कार्रवाई की जा रही है। हम सरकार के सारे नियम को पूरा करके अस्पताल चला रहे हैं। हमने 2018 में उदयपुर विकास प्राधिकरण में इसके लिए आवेदन कर दिया लेकिन इसके बावजूद भी तय समय में स्वीकृत नहीं दी। सरकार के नियम है कि अगर 3 महीने में स्वीकृत नहीं आती तो वह स्वतः स्वीकृति मानी जाती है। जीबीएच के मैनेजर ऑपरेशन विजित दिवाकर ने बताया कि फूल सिंह मीणा ने बदले की भावना से इसे विधानसभा में उठाकर कार्रवाई करवाई है। वर्तमान में अस्पताल के आईसीयू में 72 मरीज है। जनरल अस्पताल को सीज करते है तो यहां मरीजों को संभालने की क्या व्यवस्था होगी। उनका आरोप है कि फूल सिंह मीणा के मिलने वाले चेतन मीणा नामक व्यक्ति को यहां हमने गलत काम करते हुए पकड़ा और प्रबंधन ने उसे हटा दिया था। उन सबके बहकावे में आकर विधायक इस तरह के मुद्दे उठा रहे हैं।

मंत्री ये जवाब दिया था

उदयपुर कलेक्टर ने 24 जुलाई 1998 को गिर्वा तहसील के बेड़वास में 69 हजार 650 वर्ग मीटर भूमि 99 साल की अवधि के लिए आवंटित की और निर्माण स्वीकृति में दो साल में निर्माण करने की शर्त थी। इसके बाद 6 दिसंबर 1999 को 7500 वर्ग मीटर को दूसरी बार जमीन का आवंटन कलेक्टर उदयपुर ने किया।

12 जुलाई को दिया था नोटिस

मंत्री खर्रा ने कहा कि वहां जो निर्माण स्वीकृति जारी की उससे ज्यादा निर्माण अमेरिकन इंटरनेशनल हेल्थ मैनेजमेंट लिमिटेड ने किया। 12 जुलाई को अवैध निर्माण को लेकर नोटिस भी जारी किया था। सदन में दी गई थी स्वीकृति सदन में 22 को मंत्री ने अवैध निर्माण की जानकारी सदन में रखते हुए कहा कि भूतल प्लस चार तल, भूतल प्लस तीन तल और पांच भवनों को भूतल प्लस दो तल का और दो भवनों की भूतल निर्माण स्वीकृति जारी की गई थी। उन्होंने बताया कि इस पर भूतल स्वीकृति वाले का निर्माण नहीं किया ओर शेष में नियम के विपरीत अतिरिक्त निर्माण कर लिया गया।

ये अवैध निर्माण बताए थे मंत्री ने

मंत्री ने विधानसभा में बताया कि वहां पर बिना स्वीकृति के नर्सिंग हॉस्टल, भूतल प्लस 8 तल और प्रोफेसर भवन अवैध रूप से बना दिए। उन्होंने कहा कि यहीं नहीं अमेरिकन इंटरनेशनल हेल्थ मैनेजमेंट ने उक्त अनियमितता के साथ राजस्थान माइंस एंड मिनरल्स लिमिटेड और एमबी अस्पताल उदयपुर के साथ भी धोखाधड़ी और जालसाजी करने की शिकायत प्राप्त हुई उसकी प्रारंभिक जांच में सत्यता प्रतीत होती है।

एक समिति की भी घोषणा की थी

मंत्री ने उस दिन सदन में घोषणा करते हुए कहा कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में यूडीएच, स्वास्थ्य और मिनरल्स विभाग के साथ एक उच्च स्तरीय समिति गठित कर चार या पांच सप्ताह में रिपोर्ट प्रस्तुत करें। साथ ही वहां पर बिना निर्माण के जितने भी निर्माण हुए संबंधित निकाय उनको 72 घंटे में सीज कर विधानसभा सचिवालय को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

ग्रामीण विधायक फूलसिंह मीणा ने उठाया था मुद्दा

दरअसल, विधानसभा में 22 जुलाई को उदयपुर ग्रामीण विधायक फूलसिंह मीणा ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरिए बेड़वास के इस हॉस्पिटल का मामला उठाया था। इस पर राज्य सरकार की ओर से यूडीएच मंत्री खर्रा ने सदन में जवाब देते हुए कहा था कि 72 घंटे में अवैध बने भवनों को सीज कर दिया जाएगा और इसकी पालना कर संबंधित एजेंसी को विधानसभा सचिवालय को सूचित करना होगा।

राजस्थान में पहली ऐसी सर्जरी, जिसमें महाधमनी को बदल दिया

हार्ट को खून सप्लाई करने वाली आर्टरी की रटर में हुई सर्जरी

द पुलिस पोस्ट

जयपुर। 62 साल की महिला के महाधमनी (हार्ट मेन आर्टरी) में हुए छेद को रटर के डॉक्टरों ने 12 घंटे चले ऑपरेशन के बाद ठीक किया है। डैमेज हो चुकी हार्ट मेन आर्टरी को रिपेयर करने के साथ ही एरोटिक आर्च (महाधमनी चाप) को भी रिप्लेस किया गया है। हॉस्पिटल के डॉक्टरों का दावा है कि इससे पहले राजस्थान में हार्ट की ऐसी सर्जरी कहीं नहीं हुई है। इस तरह की सर्जरी के लिए दिल्ली या दूसरे बड़े शहर जाना पड़ता था। रटर के 15 डॉक्टरों की टीम ने 22 जुलाई को यह ऑपरेशन किया। सर्जरी 12 घंटे तक चली।

मरीज के सीने में उठा था तेज दर्द

एसएमएस हॉस्पिटल में कार्डियोथेरेसिक सर्जरी डिपार्टमेंट के सीनियर प्रोफेसर डॉ. राजकुमार यादव ने बताया कि जोधपुर के पास फलोदी की रहने वाली 62 साल की सुआ कंवर का ऑपरेशन किया गया। महिला को करीब 20-22 दिन पहले अचानक सीने में तेज और कमर में दर्द उठा था। दर्द के बाद महिला को फलोदी के हॉस्पिटल में लेकर गए। वहां से उसे जोधपुर एम्स में भर्ती किया गया। एम्स में जांच की गई। पता चला कि महिला के हार्ट को खून सप्लाई करने वाली मेन आर्टरी (महाधमनी) डैमेज यानी उसमें

62 साल की महिला की महाधमनी में छेद था

छेद या दरार आ गई है। इसके साथ ही एरोटिक आर्च में भी परेशानी होने लगी। जोधपुर एम्स के डॉक्टरों ने इतना बड़ा ऑपरेशन करने में असमर्थता जताई। उन्होंने एसएमएस या दिल्ली एम्स ले जाने की सलाह देते हुए रेफर कर दिया। 5 दिन पहले ही महिला को यहां रटर लाया गया था। इसके बाद 22 जुलाई को ऑपरेशन किया गया।

12 घंटों में 10 यूनिट ब्लड चढ़ाया

डॉक्टर यादव ने बताया कि इस पूरे ऑपरेशन को करने में टीम को 12 घंटे का समय लगा। ऑपरेशन के दौरान ब्लड लॉस ज्यादा था और समय भी ज्यादा लग रहा था। इस कारण मरीज को ऑपरेशन के दौरान ही 10 यूनिट ब्लड चढ़ाया गया। इस पूरे ऑपरेशन के दौरान मरीज के दिमाग का कंट्रोल बनाए रखने के लिए उसे परफ्यूजन डबल कैनुलेशन के जरिए परफ्यूजन ठक्कर से मॉनिटर किया गया। उन्होंने बताया कि मरीज ऑपरेशन के बाद ठीक है। आईसीयू में अभी डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया है।

15 डॉक्टरों की टीम लगाई

प्रोफेसर डॉ. राजकुमार यादव ने बताया- सर्जरी करने वालों में डॉ. रीमा, अंजुम, डॉ. राजेश शर्मा, मौलिक शर्मा, पुलकित आचार्य, सुलोचना, पूजा, नवदीप, संदीप, गजला, डॉ. जसकरण, चित्रा, रागिनी, सुहानी, प्रीतांशी, राकेश और कादिर शामिल थे।

अलवर यूआईटी ने नेता प्रतिपक्ष जूली को माना अतिक्रमी: विधानसभा में एमएलए ने यूआईटी की रिपोर्ट दिखाई,

'सरिस्का के आसपास जमीन आवंटन का मामला भी उठाया

द पुलिस पोस्ट

अलवर। कांग्रेस सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे और वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली को अलवर वक्फ ने अतिक्रमी माना है। विधानसभा में विधायक के सवाल के जवाब में यूआईटी ने रिपोर्ट दी, जिसमें प्रेम रत्नाकर बांध के बहाव क्षेत्र में अतिक्रमियों की सूची जारी की। इस सूची में क्रमांक पर टीकाराम जूली का नाम है। स्पष्ट लिखा है कि इन्होंने चारदीवारी कर अतिक्रमण किया है। अब इस रिपोर्ट पर बवाल मच गया है। सूची में कुल 13 अतिक्रमी हैं।

केकड़ी के विधायक ने विधानसभा में दिखाई रिपोर्ट

केकड़ी के विधायक शत्रुधन गौतम ने विधानसभा में रिपोर्ट दिखाते हुए कहा- अलवर के प्रेम रत्नाकर बांध भराव क्षेत्र में अतिक्रमण हुआ है, जिसकी रिपोर्ट भी विधानसभा में यूआईटी ने दी है। उस रिपोर्ट के अनुसार नेता प्रतिपक्ष का नाम अतिक्रमी के रूप में दिखाया है। यदि यह रिपोर्ट सही है तो नेता प्रतिपक्ष को जवाब

देना चाहिए। यदि रिपोर्ट गलत है तो जिम्मेदार अधिकारी व कर्मचारियों के खिलाफ एक्शन लिया जाए। इसके अलावा विधायक ने पिछली कांग्रेस सरकार में सरिस्का टहला के आसपास करीब 2 हजार बीघा जमीन के आवंटन का मामला उठाया। जिसमें नदी नालों के बहाव क्षेत्रों को आवंटित कर दिया। इस मामले में सरकार ने कार्यवाही करने का आश्वासन भी दिया।

रिपोर्ट में इन अतिक्रमियों के नाम

प्रेम रत्नाकर बांध के बहाव क्षेत्र में अतिक्रमियों की सूची में केके शर्मा ने कटीघाटी से पश्चिम की तरफ श्याम नगर कॉलोनी अवैध निर्माण, प्रमोद आर्य ने कटी घाटी बाउंड्री व पौधारोपण, मंजू नरूका पत्नी जयवीर सिंह ने कटी घाटी से उतरकर पश्चिम की तरफ श्याम नगर कॉलोनी मकान निर्मित है। पुष्पा देवी पत्नी रणवीर सिंह ने कटीघाटी के पास मकान बना लिया। टीकाराम जूली ने कटीघाटी से उतरकर श्यामनगर कॉलोनी में बाउंड्री की है। शौकीन पुत्र भूपला मेव ने कटी घाटी से उतर कर श्याम नगर में बाउंड्री, मंजू पत्नी मुकुल चंद यादव ने श्याम नगर में मकान बना है। किशनलाल पुत्र नारायण लाल मीणा ने बाउंड्री बना ली। पप्पू पुत्र छोटे लाल ने श्याम नगर कॉलोनी में मकान बना लिया। रामकुमार पुत्र छोटे लाल ने श्याम नगर में मकान निर्माण कर लिया। उम्मेद सिंह पुत्र केशव सिंह ने श्याम नगर में मकान बना लिया। मुकेश प्रजापत पुत्र प्रेम चंद प्रजापत श्याम नगर में मकान बना लिया है।

हो चुके कई निर्माण

यूआईटी ने 2012 की सर्वे रिपोर्ट का हवाला देकर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली व अन्य लोगों को अतिक्रमी माना है। अब तो मौके पर मैरिज होम, होटल, सैकड़ों मकान प्रेम रत्नाकर बांध के बहाव क्षेत्र में बन चुके हैं।

स्वात्वाधिकारी, प्रकाशक एवं मुद्रक संपादक उपेन्द्रसिंह राठौड़, अम्बर ऑफसेट प्रा.लि.डीएल टॉवर, 3ए, विद्याश्रम संस्थानिक क्षेत्र जेएलएन मार्ग जयपुर से मुद्रित एवं भू-तल ऑरबिट मॉल, सिविल लाइंस, जयपुर (राजस्थान) से प्रकाशित, 99280-96524, पीआरबी एक्ट के तहत जिम्मेदार, अनिल मलिक (सहसंपादक) 8696750000, पंकज गर्ग (प्रबंध संपादक) 01482-455184, 9214417111